A Daily News Magazine
भोपाल
सोमवार, 03 मार्च, 2025

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 175, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

पहली बात

वसंतोत्सव में कोयल की कुहुक 'म्यूट' होने के मायने

उमेश त्रिवेदी
प्रधान संपादक

व्हाइट हाउस के ओवल-ऑफिस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की के उखड़े और टूटे पिच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सवालों के बाउन्सर फेंक कर सुर्खियां बटोरने वाली आसान अखबारनवीसी के सामने कतिपय उतने ही महती सवाल मौजूद हैं, जो भारत की अपनी जमीन तोड़ने पर आमादा हैं। लेकिन समाज को हर पल टोकने वाले ये सवाल मीडिया में नदारद हैं। निजी पलछिनों की स्नेहिल तरलता में गुनगुनाते बसंत के आनंदोत्सव में यदि सहसा मन में यह सवाल कसमसाने लगे कि इस बार तो कोयल की कुहुक ही सुनने को नहीं मिली... क्या इस बसंत में कोयलों का हमारे शहर में आना-जाना नहीं हुआ...कोयलों की इस बेरूखी का सबब क्या है ? सवालों की तफ्तीश यह है कि जेलेंस्की-ट्रम्प के कूटनीतिक बैक-ड्रॉप में पंछियों या कोयलों की कुहुक 'म्यूट' हो जाने की घटनाओं से हमें कितना चिंतातुर होना चाहिए ?

भारत में ऋतु-चक्र की गतिमान भाव-भूमि पर एक अजीबो-गरीब सहमेपन के साथ रंगों का ऋतुओं के राजा वसंत का वसंतोत्सव जारी है। वसंत अंतर्मन की गहराइयों को गोते लगाकर रूमानियत के सभी जज्बों को उद्वेलित और उत्प्रेरित करता है। लेकिन हवाओं की ठिठुरन और ठंडक में गुनगुनापन घुलने के बावजूद फिजाओं में रौनक कमतर महसूस होने लगी है। वैसे वसंत फूलों की खिलखिलाहट और पंछियों की चहचाहट का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इन दिनों कोयल की कुहुक और पंछियों का कलरव मंद सुनाई पड़ता है। हमने अपनी हवाओं के दरवाजे खुद ही बंद कर लिए हैं। मौसम आते हैं, चले जाते हैं, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। पुरवैया हवाओं के बहाव में सीमेंट के जंगल आड़े आ रहे हैं। पछुआ हवाओं के रास्तों मे कठोर भंगार जमा है। वसंत की अगवानी में कोयल कुहुक नदारद है। वसंत यह सवाल पूछ रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?

कोयल का कुहुकना एक जज्बाती करिश्मा है। कोयल यूं ही हमारे जहन का हिस्सा नहीं है। कोयल के कुहुकने के मायने कई हैं। यह प्रतीकात्मक है। मनोभावों के रंगमंच पर कुहुकने का 'कोयलिया-कोरस' अंतरमन में हिलोरे पैदा करता महसूस होता है...कोयल कुहुकती है तो विरहाग्नि धधक उठती है...कोयल कुहुकती है तो प्रकृति की पीली-पीली चोली फाड़कर बसंत का यौवन फूट पड़ता है...कोयल कुहुकती है तो नदियों के निनाद में प्रणय का उत्सव शुरू हो जाता है...कोयल कुहुकती है तो आसमान में रंग भरने लगते हैं... कोयल कुहुकती है तो जंगलों में पलाश के फूल होली की रसीली फुहारों का आश्वासन देने लगते हैं... इसलिए कोयल की कुहुक का गुम हो जाना सहज प्राकृतिक उत्पात नहीं है...। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

बहलहाल, आम जिंदगी के स्क्रीन पर कोयल की कुहुक के 'म्यूट' हो जाने को हमारे जैसे कई लोगों ने महसूस किया होगा...। लेकिन हमारे आसपास सिर्फ कोयल की गुमशुदगी ही सवालों के घेरे में नहीं है। जिंदगी के स्क्रीन पर सिर्फ कोयल का कुहुकना ही 'म्यूट' नहीं हुआ है... पपीहों का टेरना भी 'म्यूट' हुआ है... गौरैया का चहकना भी 'म्यूट' हुआ है... घर की मुंडरों पर कौओं की कांव-कांव भी 'म्यूट' हुई है...। हमारी जिंदगी की सुनहरी सुबहों और सलोनी सांझों को संगीत की रूबाइयों में तब्दील करने वाले अनगिन पंछी और उनकी आवाजें कहां और क्यों गुम होने लगी हैं ? क्यों 'म्यूट ' होने लगी हैं?

ये सवाल व्यक्ति के निजी, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में पूरी शिद्दत से मौजूद हैं। रोजमर्रा जिंदगी के विमर्श में इनकी व्यापकताएवं गंभीरता गहरी हैं,किन्तु नीति-नियंताओं की बौद्धिक-बधिरता के धुंधलकों ने इन्हें काफी नीचे ढकेल दिया है। सिर्फ देश के नीति-नियंता ही नहीं, समाजिक संवेदनाओं के पथरीलेपन ने भी इन सवालों को हाशिए पर ढकेला है। सवाल सीधे हैं... इर्द-गिर्द पूरी ढिठाई से मौजूद हैं...साथ चलते हैं...पीछे दौड़ते हैं...मिन्नतें करते हैं...हाथ पकड़ कर अपना ठिकाना पूछते हैं...सवालों का दर्द बेइंतिहा है...उन्हें लावारिस छोड़ना जिंदगी को दोजख में ढकेलना है।

खेतों में गेहूं की बालियां बौराने लगी हैं और जंगलों में पेड़ो पर फूलते ''पलाश'' के फूलों में तोते का अक्स देखकर वेदों के रचयिता पूछने लगे है 'किम्ज्शुकः ! याने क्या यह तोता है'? वेदों और संस्कृत की कविताओं के रचयिता पलाश की पांखुरियों में तोते की नाक के आभास पाकर भले ही पूछते हों कि किंशुक याने क्या यह तोता है, लेकिन हमारे मन मे यह सवाल नहीं उठ रहे हैं कि पंछियों के संसार बेजार क्यों होता जा रहा है?

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (जे.एस. आई.) के अध्ययन के अनुसार भारत में पक्षियों की कुल 78 प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया में 10 हजार 906 पक्षी-प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें 1353 प्रजाति के पंछियों का घर भारत में है। सिर्फ भारत में पाई जाने वाली पंछियों की 78 प्रजातियों मे से 25 लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में पक्षियों की स्थिति पर 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 30 सालों में भारत में पक्षियों की संख्या में लगभग 60 फीसदी गिरावट आई है। यह गिरावट जैव विविधता के गंभीर नुकसान को रेखांकित करती है। यह पर्यावरण पर मनुष्य जनित दबाव का खतरनाक संकेत है। पक्षियों की घटती आबादी के कारणो में सबसे ऊपर पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका को माना गया है। वनों के विनाश, शहरीकरण, अवैध शिकार के कारण भी पंछियों का आबादी पर असर पड़ा है।

पंछियों के ये पतले हालात उस वक्त हैं, जबकि भारतीय परम्परा में पक्षियों को विशेष सम्मान रेखांकित है। उनका महत्व समाज का स्थायी भाव है। इनके नाम देवताओं के साथ दर्ज हैं। 'गरूड़' को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। जबकि ब्रम्हा और सरस्वती श्वेतवर्णी 'हंस' पर विराजमान दिखते हैं। कामदेव 'तोते' की सवारी करते हैं तो कार्तिकेय को 'मयूर' पसंद है। लक्ष्मी का वाहन 'उल्लू' है। इन्द्र और अग्नि की सवारी 'अरूण-कुंच' पक्षी मानी जाती है, जिसे 'फ्लेमिंगो' भी कहते हैं। वरूण का वाहन 'चकवाक' पक्षी है, जिसे शैडलक कहा जाता है।

वेदो में पक्षियों की महत्ता निर्विवाद रही है। ऋग्वेद के मंत्रों में वृक्ष पर बैठे दो 'सुपर्णो' के रूपक से जीव और आत्मा का अंतर समझाया गया है। अथर्ववेद में 'चकवा' नाम के पक्षी को 'निष्ठावान' का प्रतीक माना गया है। ऋग्वेद में 20और यजुर्वेद में 60 किस्म के पक्षियों का उल्लेख मिलता है। भारतीय लोक-साहित्य चातक, चकोर, पपीहा, तोता-मैना,हंस कबूतर, को अलग-अलग गीतों और रूपको में बखाना गया है। 'हंस' को प्यार और शुचिता का प्रतीक है, और आदर्श दाम्पत्य जीवन के रूपक के रूप में इसकी व्याख्या होती है। माना जाता है कि 'हंस' के जोड़े में किसी एक की मृत्यु हो जाने के बाद दूसरा 'हंस' अपना जीवनएकाकी ही गुजारता है। 'नीलकंठ' को शिव का प्रतीक माना गया है, जबकि 'मोर' भगवान कृष्ण को प्रिय थे। 'गरूड़' को बुद्धिमान पक्षी माना जाता है। पौराणिक कथाओं मे 'तोता' महापंडित के रूप में महिमामंडित है वास्तुशास्त्र में तोते के चित्र का बड़ा महत्व है। 'कपोत' या 'कबूतर' शांति के प्रतीक संदेशवाहक माने जाते हैं। 'गौरेया' को घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि का परिचायक माना जाता है। जबकि कोयल की कुहुक से संगीत का समां बंध जाता है। पंछियों की इन परिकल्पनाओं के बीच उनके साथ मानवजनित ज्यादतियों के सवाल दुरूहता बढ़ाने वाले हैं। इनका निराकरण जरूरी है।

सुप्रभात

बने सुनायी गाँव की गोरी की दास्ताँ
हमने सुनायी कर्ज़ की होरी की दास्ताँ
लेकर के चल दिए सभी मेरे शरीर को
पंखा सुनाता रह गया डोरी की दास्ताँ
जब खिड़कियों से ख़त कोई देकर नहीं गया
फिर तो सुनाना व्यर्थ है मोरी की दास्ताँ
आँसू निकल पड़े हैं जो ज़ोरों की भूख से
दादी सुनाती दाल की झोरी की दास्ताँ।

– अमन मुसाफ़िर

सोमनाथ में पीएम मोदी ने की प्रथम ज्योतिर्लिंग की पूजा

मोदी आज द्वारका और गिर जिलों का करेंगे दौरा

पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र 'वनतारा' भी देखा

जामनगर (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तीन दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे हैं। रविवार सुबह करीब 11 बजे पीएम जामनगर में स्थित रिलायंस द्वारा संचालित पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र 'वनतारा' पहुंचे। वनतारा का दौरा करने के बाद शाम करीब 5.00 बजे सोमनाथ पहुंचे।

यहां प्रथम ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने के बाद 27 करोड़ रुपए से तैयार किए गए हाईटेक मार्केट का उद्घाटन किया। पीएम सोमवार को जामनगर, द्वारका और गिर जिले में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। रविवार सुबह करीब 11 बजे पीएम जामनगर में स्थित रिलायंस द्वारा संचालित पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र 'वनतारा' पहुंचे। गौरतलब है कि जामनगर में जानवरों के पुनर्वास के लिए बनाया गया 'वनतारा' दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत का ड्रीम प्रोजेक्ट है।

3000 एकड़ ग्रीनबेल्ट में फैला हुआ है 'वनतारा'

लायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वनतारा (स्टार ऑफ फॉरेस्ट) कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, घायल जानवरों का बचाव, उपचार, देखभाल और उनका पुनर्वास शामिल है। वनतारा रिलायंस के जामनगर स्थित रिफाइनरी परिसर के 3000 एकड़ ग्रीनबेल्ट में फैला हुआ है। वनतारा प्रोजेक्ट जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है।

एमपी में किसानों को सीएम ने दी बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री बोले-किसानों को 30 लाख सोलर पंप भी देंगे

पांच रुपए में मिलेगा बिजली कनेक्शन

भोपाल। मध्यप्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इसका रविवार को ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह योजना मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू की जाएगी। इसके बाद पश्चिम क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। सीएम डॉ. यादव भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने की योजना बना रही है। अगले तीन साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। इससे दिन में भी बिजली मिलेगी। सीएम ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी। बता दें कि अभी खेतों में बिजली कनेक्शन लेने पर किसानों को सालाना 7 हजार 500 रुपए रुपए चुकाने पड़ते हैं। सीएम ने कहा, भारत की साख बढ़ाने के लिए किसानों का जीवन सुखी और समृद्ध बनाना जरूरी है।

उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के बारे में कहा कि, पहले लोग तार पकड़ लेते थे, लेकिन करंट नहीं आता था। पहले गांवों में न बिजली थी, न सड़कें। नगरों में पेयजल, खेतों को पानी और उद्योगों को पानी दिया जा सकता था। लेकिन जब हम उज्जैन में सिंहस्थ के लिए नर्मदा का पानी मांगते थे, तो दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में कहा था कि यह असंभव है। शिप्रा ऊंचाई पर है और नर्मदा नीचे, इसलिए यह आ ही नहीं सकती। लेकिन आज नर्मदा-शिप्रा लिंक बन चुका है।

सीएम को हल, बैलगाड़ी और गेहूं की बालियां भेंट की

किसान आभार सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दर्शन सिंह चौधरी, कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद थे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री को हल, बैलगाड़ी और गेहूं की बालियां भेंट की गईं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार किसानों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा उनके लिए सोचती है। उन्होंने कहा कि विभाग के मंत्री को बाद में अखबार से पता चलता है कि क्या फैसला हो गया। सीएम ने कहा कि इस बार खरीदी के दौरान गर्मी में किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पानी और छाया की व्यवस्था केंद्रों पर की जाएगी।

स्कूली शिक्षा में जोड़ना चाहिए कानून की पढ़ाई : जस्टिस अनिल वर्मा

विक्रमादित्य का न्याय वैचारिक समागम में दूसरे दिन न्याय प्रक्रिया पर मंथन

उज्जैन में विक्रमोत्सव

उज्जैन से डॉ. जफर महमूद

विक्रमोत्सव के अंतर्गत तीन दिवसीय विक्रमादित्य के न्यायिक समागम के दूसरे दिवस के प्रथम सत्र में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने कहा कि न्याय तंत्र हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। न्याय लोकतंत्र में और अहम हो गया है। राजतंत्र में विक्रमादित्य के समय भी न्याय व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। उनका नाम विश्व इतिहास में महान न्याय सम्राट, चक्रवर्ती शासक और विद्वानों के संरक्षक के रूप में अंकित है। विक्रमादित्य सत्य और निष्ठावान पराक्रमी शासक के रूप में विख्यात थे। उनके बाद भी कोई अच्छा न्याय करता तो कहा जाता था की विक्रमादित्य की पीठ पर बैठकर न्याय कर रहा है। विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में अमानवीय कृत्यों को बंद किया था। उनकी न्याय व्यवस्था दंड देने के बजाय सुधारने पर विश्वास करने वाली व्यवस्था थी। न्याय की अवधारणा के प्रति उनकी प्रणाली आज भी प्रासंगिक है। उनकी न्याय की गाथाएं आज भी किंवदंतियों के रूप में प्रचलित हैं। हम विक्रमादित्य शोध पीठ से अनुरोध करते हैं कि उन्हें संकलित कर शीघ्र प्रकाशित करें, जिससे न्याय व्यवस्था को प्रकाश प्राप्त हो। न्यायाधीश को आसंदी पर बैठने के बाद ईश्वरीय प्रेरणा रहती है। आसंदी पर बैठा न्यायाधीश आम आदमी नहीं रहता। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य का यह मानना था कि निर्णय से अपराधी में परिवर्तन आना चाहिये। हमारी लोक अदालत विक्रमादित्य की न्याय पद्धति पर आधारित हैं। वर्तमान समय में भारतीय समाज में पारिवारिक तनाव बढ़ रहे हैं। संपत्ति विवाद बढ़ रहा है। समाज में सद्भावना और सदाचार की आवश्यकता है। विक्रमादित्य के समय में न्याय सभाएं होती थीं। धर्म शास्त्री सही निर्णय देने के लिए मददगार होते थे। वर्तमान समय में शीघ्र और त्वरित न्याय मिले इस पर चिंता के जाना चाहिये। जिला स्तर पर न्यायालय में बहुत सुधार आया है। अब तेज गति से निर्णय होने लगे हैं। जीवन में कानून हर समय काम आता है। हमारी स्कूली शिक्षा में कानून को जोड़ा जाना चाहिये। हमारे न्यायाधीश हर फाइल को व्यक्ति माने तो मानवीय दृष्टिकोण फलीभूत होगा।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आईएस श्रीवास्तव ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिये। प्राचीन काल से हमारे देश में हर क्षेत्र में समृद्धि का वातावरण रहा है। घर से ही बच्चा सीखता है । बच्चों को घर में ही शिक्षित दीक्षित करें। हमें पुनः अपनी संस्कृति की ओर लौटाना होगा। विक्रमादित्य पर परमात्मा का अंश था। हमारी न्याय प्रणाली प्राचीन काल से ही समृद्ध न्याय प्रणाली रही है। विक्रमादित्य से लेकर आज तक वही न्याय प्रणाली है। न्याय करने वाले न्यायाधीश को तपस्वी का जीवन जीना पड़ता है। हमारी न्याय व्यवस्था में न्यूनतम से अधिकतम की व्यवस्था है। सजा को निश्चित नहीं किया गया है। न्यायाधीश के विवेक को महत्वपूर्ण माना गया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीके व्यास ने कहा कि विक्रमादित्य की न्याय व्यवस्था आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। विक्रमादित्य को न्याय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा के दंड को जोड़ा गया है। हम न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वह दोषी पक्षकार के दंड के लिए सामुदायिक सेवा का आग्रह किया करें। 1873 के भारतीय शपथ अधिनियम को विधि आयोग की 28वीं रिपोर्ट के बाद 1969 में धर्म ग्रंथों का अपमान मानकर बंद कर दिया था गया था। समागम में हम आग्रह करते हैं कि वर्तमान समय में धार्मिक आस्था में परिवर्तन हुआ है। भारतीय शपथ अधिनियम को लागू किया जाना चाहिये। जिससे कि भारतीय न्याय व्यवस्था में धार्मिक आस्था को पुर्नस्थापित किया जा सके।

संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति अनिल वर्मा

उन्होंने कहा कि पीड़ित प्रतिकर योजना में समुचित प्रतिकर का प्रावधान होना चाहिए। लूट,चोरी, डकैती पर विक्रमादित्य के समय प्रचलित दिग्दंड के लिए पुलिस को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम का संचालन विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सलाहकार चंद्रेश मंडलोई ने किया। आभार उज्जैन बार कॉल काउंसिल के अध्यक्ष अशोक यादव ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के आरंभ में कवि दिनेश दिग्गज ने सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित ओजस्वी कविता का पाठ किया। इस अवसर पर डॉ निशा केवलिया, सुश्री नीता निपुण सक्सेना, विश्वजीत सिंह चौहान, संतोष मालवीय,डॉ अजय शर्मा, शेखर श्रीवास्तव, दुर्गेश साहू, डॉ अरुण सेठी डॉ जफर महमूद, डॉ चंद्र दीप यादव,डॉ प्रशांत पुराणिक, डॉ रमण सिंह सोलंकी, डॉ प्रदीप लाखरे सहित विधि विशेषज्ञ एवं शोधार्थी उपस्थित थे।

चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया

वरुण चक्रवर्ती ने 42 रन देकर लिए पांच विकेट, श्रेयस अय्यर ने खेली 79 रन की अर्धशतकीय पारी

दुबई, (भाषा) । भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी मैच में रविवार को यहां न्यूजीलैंड को 44 रन से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया।भारत ने नौ विकेट पर 249 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड को 205 रन पर आउट कर दिया कर दिया।

भारत के सामने सेमीफाइनल में मंगलवार को दुबई में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती होगी जबकि न्यूजीलैंड का सामना बुधवार को लाहौर में दक्षिण अफ्रीका से होगा।

भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर में 42 रन देकर पांच विकेट लिये। कुलदीप यादव को दो सफलता मिली।न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन ने 81 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। इससे पूर्व श्रेयस अय्यर (79) की अर्धशतकीय पारी के बावजूद मैट हेनरी की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड ने भारत को नौ विकेट पर 249 रन पर रोक दिया। हेनरी ने आठ ओवर में 42 रन देकर पांच विकेट लिये। उन्हें टीम के दूसरे गेंदबाजों अच्छा साथ मिला। न्यूजीलैंड के लिए काइल जैमीसन, विलियम ओ'राउरकी, कप्तान मिचेल सेंटनर और रचिन रविंद्र ने एक-एक विकेट लिये। न्यूजीलैंड के क्षेत्ररक्षकों ने कुछ कमाल के कैच पकड़ने के साथ अहम रन बचाये। भारत ने शुरुआती सात ओवर में 30 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे लेकिन अय्यर ने 98 गेंद की पारी में चार चौके और दो छक्के की मदद से 79 रन की संयमित पारी खेलने के अलावा अक्षर पटेल (42) के साथ चौथे विकेट के लिए 136 गेंद में 98 रन की साझेदारी कर टीम को खराब शुरुआत से उबारा। उन्होंने लोकेश राहुल (23) के साथ भी 42 गेंद में 44 रन की साझेदारी की। अक्षर ने 61 गेंद की पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। आखिरी ओवरो में हार्दिक पंड्या ने 45 गेंद में चार चौके और दो छक्के की मदद से 45 रन बनाकर टीम को 250 रन के करीब पहुंचाया।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 22 °c
न्यूनतम 16°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार,03 मार्च 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

शेहला राशिद पर अब नहीं चलेगा देशद्रोह का मुकदमा

एलजी ने केस चलाने की मंजूरी वापस ली

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला राशिद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा वापस लेने की मंजूरी दे दी। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने 27 फरवरी को अभियोजन पक्ष की ओर से दायर एप्लीकेशन पर यह आदेश दिया। एप्लीकेशन के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने शेहला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी वापस ले ली है। एलजी ने 23 दिसंबर, 2024 को शेहला पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। अब एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर यह मंजूरी वापस ले ली है।

जयपुर में शाहरुख ,माधुरी व शाहिद अपने नाम के लगाएंगे पौधे

8 मार्च से समारोह

जयपुर (एजेंसी)। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी (आईफा-25) अवॉर्ड्स इस बार खास होंगे। जयपुर में 8 और 9 मार्च को होने जा रहे इन अवॉर्डस से पहले बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटी एक आईफा गार्डन भी बनाएंगे। करीब 15 हजार पौधों से तैयार होने वाले इस गार्डन में शाहरुख खान, माधुरी

दीक्षित, शाहिद कपूर और कार्तिक आर्यन भी पौधे लगाएंगे। इन पौधों का नाम भी स्टार्स के नाम पर रखा जाएगा। जयपुर के जेईसीसी बनने वाले इस गार्डन के अभियान में आम लोग भी जुड़ सकते हैं। वहीं, आईफा अवॉर्ड का इनविटेशन कार्ड भी जयपुर में ही डिजाइन किया गया है। करीब 7 किलो वजन वाले इस कार्ड में जयपुर के फेमस टूरिस्ट प्लेस और आर्टिफैक्ट्स की भी झलक है। इंडियन फिल्म एकेडमी के मेंटरशिप में चैलेंज फॉर ग्रीन पहल के तहत पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें आम लोग भी जुड़ सकते हैं। इसका उद्घाटन अवॉर्ड शो के दिन किया जाएगा।

जादवपुर विवि में छात्र संघ चुनाव की मांग पर हंगामा

छात्र घायल हुआ

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में तत्काल छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर हंगामा हुआ। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सहित दूसरे स्टूडेंट फ्रंट्स ने राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु का घेराव किया। उनकी कार की पीछा किया। दावा किया गया कि इस दौरान मंत्री की कार में तोड़फोड़ की गई। हालांकि एसएफआई ने इस आरोप को गलत बताया है। दरअसल, शिक्षा मंत्री बसु पश्चिम बंगाल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ

की सालाना होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए कॉलेज पहुंचे थे। एसएफआई और दूसरे स्टूडेंट फ्रंट्स को जब इसकी जानकारी मिली तो वे अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच गए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स उस हॉल के बाहर जुटने लगे जहां संघ की बैठक होने वाली थी। मंत्री को इसकी जानकारी मिली तो दूसरे गेट से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। बाद में उन्होंने स्टूडेंट्स से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने उन्हें घेर लिया और अपना डिमांड लेटर सौंपा। मंत्री छात्रों की पूरी बात सुने बिना जाने लगे तो टकराव बढ़ गया।

महिला कबीर यात्रा का भोपाल में समापन

भोपाल। संस्था एकलव्य फाउंडेशन एवं अनंत मंडी के सहयोग से धरती की बानी हेलियों की जुबानी-मालवा महिला कबीर यात्रा वर्ष 3 का भोपाल के गौहर महल में समापन हुआ।

गौहर महल में यात्रा के समापन के अवसर पर टिमरनी की युवा गायिका शक्ति ने 'निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा' और नैहरवा कबीर की साखियों सांगीतिक शाम की शुरूआत की। उसके बाद स्नेहा, गीता पराग, राधिका सूद नायक, मंजू तंबोलिया, चारूल के साथ विनय ने अपनी वाणी से सूफ़ी परम्परा के कवियों की वाणी तथा स्त्री के जीवन अनुबवों को को पहुँचाया।

बीते चार दिनों में बंजारा सिस्टर्स, दीपांजलि डेका, विभोर समूह, मिस्टिक मंज़िल दिल्ली, चारबैत समूह से लेकर मालवा के दूर दराज के इलाकों से महिला गायिकाओं, अनाहिता, सीता बाई, लक्ष्मी और प्रीति, लक्ष्मी, सीमा बजाज, सुनीता गंगोलिया, पूजा सरोलिया, राजकुमारी सोलंकी, नीतू झारिया, सलोनी, लता, शशि, जमनाबाई के साथ अन्य ने अपनी प्रस्तुति दी है। 27 फरवरी को देवास के जैतपुरा से शुरु होकर सीहोर ज़िले के भाऊखेड़ी, नसरुल्लागंज में मंजीखेड़ी होते हुए यह गौहर महल तक की इन चार दिनों की यात्रा में सभी उम्र की, अनुभवी और उभरती 60 से अधिक महिला गायिकाओं ने शिरकत की और ज़िन्दगी की, दुख-सुख-हूक की बानी को संगीत के माध्यम से खोजा और व्यक्त किया। कबीर, नानक, मीरा, गोरखनाथ,

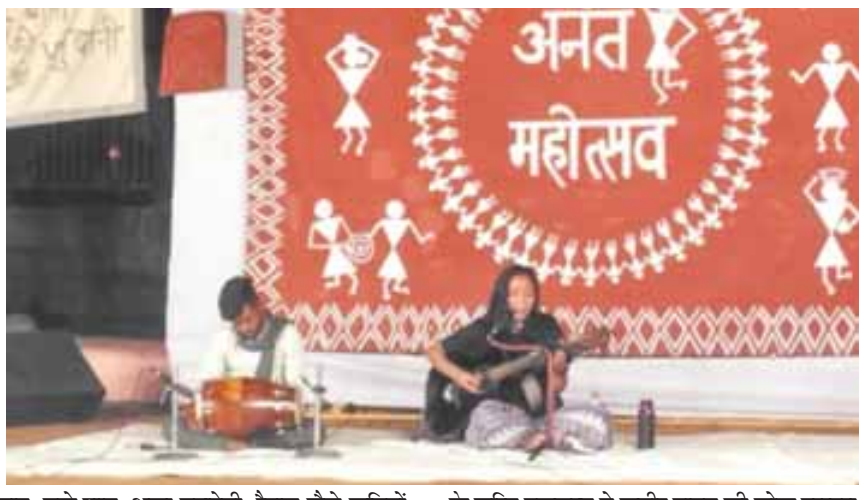

दादू, बुल्ले शाह, अक्का महादेवी, रैदास जैसे कवियों के उन गीतों की सशक्त प्रस्तुति दी जो साम्प्रदायिक सौहाद्र, एकता, महिला बराबरी, जाति व्यवस्था खत्म करने की बात करते हैं।

गौरतलब है कि मालवा इलाक़े में कबीर गायकों के साथ एकलव्य का जुड़ाव 1990 के दशक से ही रहा है। 'कबीर भजन एवं विचार मंच' (1991-1998), 'कबीर इन स्कूल्स' (2008-2009) और इसके बाद 2011 'मालवा में कबीर की वाचिक परम्पराओं के सुदृढ़ीकरण' जैसे प्रयासों के ज़रिए एकलव्य ने कबीर गायन की लोक परम्परा में विस्तार और नवाचार की कोशिशें लगातार की हैं। इसके बाद सृष्टि स्कूल ऑफ डिज़ाइन की कबीर परियोजना से जुड़कर एकलव्य ने कबीर गायन में महिला कलाकारों की भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास किए। इसमें स्कूलों में कबीर के साहित्य के माध्यम से जाति व जेंडर पर आलोचनात्मक नज़रिए की बुनियाद रखने की कोशिशें भी शामिल रहीं। इसी क्रम में एक ज़रूरी नवाचार करते हुए महिला कबीर गायकों की यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।

भोपाल परिक्षेत्र में विरासत संवर्द्धन चित्रांकन कार्यशाला

भोपाल। भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन मानव सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, जीवन शैली और उनसे संबंधित चित्रांकन के महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। विरासत की विकास यात्रा को चित्रकारों की दृष्टि से रेखांकित करने के उद्देश्य से भोपाल परिक्षेत्र में 'विरासत संवर्धन चित्रांकन कार्यशाला' आरंभ की गयी है।

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि भोपाल, रायसेन, विदिशा, नर्मदापुरम व सिहोर आदि क्षेत्रों में प्राचीन मानव सभ्यता, इतिहास, संस्कृति, जीवन शैली और उनसे संबंधित चित्रांकन के महत्वपूर्ण अवशेष मिलते हैं। यह क्षेत्र भारत के प्रागैतिहासिक वर्षों से लेकर स्वाधीनता संग्राम तक इतिहास के निर्माता और साक्षी रहे हैं। इनका इतिहास केवल रियासतकालीन नहीं है वरन इस संपूर्ण परिक्षेत्र में मानव सभ्यता की उपस्थिति प्रागैतिहासिक काल से रही है और इसके प्रमाण हमें असंख्य

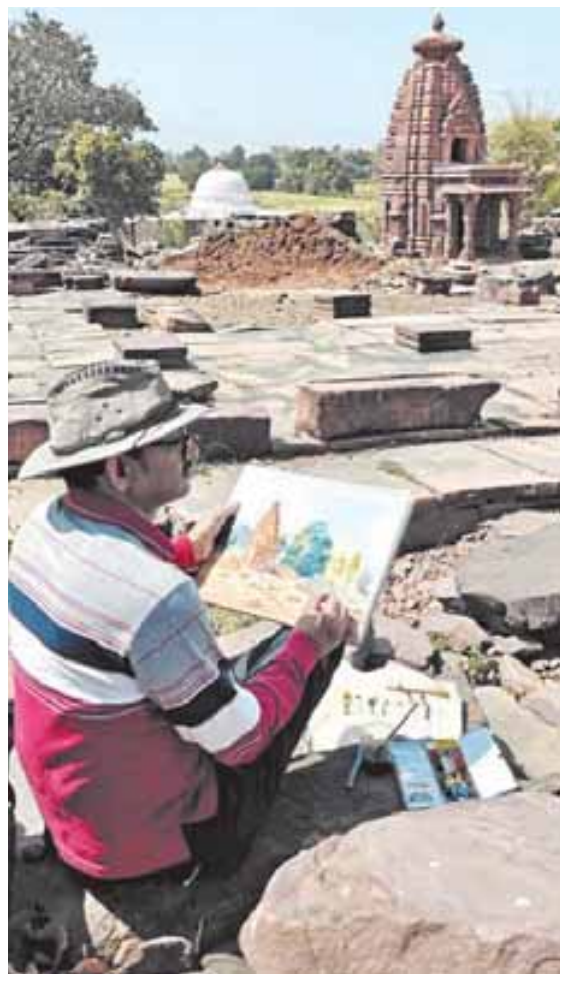

प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों से प्राप्त होते हैं।

निदेशक तिवारी ने बताया कि इस परिक्षेत्र में पाषाणकालीन सभ्यता, ताम्रपाषाणकालीन, मध्यकालीन जैन, बौद्ध, मौर्य, गुप्त, नाग, परमार व मुगल प्रत्येक काल में मानव उपस्थिति के प्रमाण बहुतायत में मिलते हैं।

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के राजा भोज शोध प्रभाग द्वारा इन विरासतों की विकास यात्रा को चित्रित कर उन्हें संवर्धित करने का कार्य शुरू किया है। इस विरासत संवर्धन चित्रांकन कार्यशाला में भोपाल के वरिष्ठ चित्रकार सर्वश्री विनय सप्रे, विवेक टेम्बे, दिनेश दुबे, प्रभु ढोक, कृष्ण कुमार मालवीय, शुभम वर्मा, विजय गहरवार, महेश शावरीकर तथा सुश्री मंजू सिंह चित्रांकन कर रहे हैं। कार्यशाला का संयोजन नितिन भांड तथा समन्वय संजय यादव द्वारा किया जा रहा है। चित्रांकन कार्यशाला के प्रथम चरण में रायसेन किले में स्थित बादल महल, रोहिणी महल, अतरदान महल, हवा महल, मस्जिद, मदरसा, सोमेश्वर शिवमंदिर और तालाब आदि भोपाल के सिद्धीक हसन की मस्जिद, कुरेशिया बेगम का मकबरा, बड़ा बाग, नजर मोहम्मद खान और उनकी बेगम के मकबरे आदि स्मारकों/स्थलों को चित्रांकित किया जा रहा है।

वत्सला चौबे को स्वयंसिद्धा सम्मान

भोपाल। हिंदी लेखिका संघ मध्य प्रदेश का तीसवां वार्षिक कृति पुरस्कार एव सम्मान समारोह 2024-25 दिनांक 2 मार्च 2025 रविवार को पंडित रविशंकर शुक्ल सभागृह हिंदी भवन में संपन्न हुआ।

संघ की अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता ने बताया कि तीसवें वार्षिक कृति पुरस्कार और सम्मान समारोह की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रविंद्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि डॉ. राजेश श्रीवास्तव और सारस्वत अतिथि शिक्षा विद डॉ. आरती दुबे थे। हिंदी लेखिका संघ द्वारा के मंच से लगभग 25 सम्मान प्रदान किए गए ।

श्रीमती कस्तूरी बाई मिश्र स्मृति स्वयंसिद्धा सम्मान सुशीला दवे, इंदौर एवं युवा लेखिका सम्मान वत्सला चौबे के कहानी संग्रह 'वत्सला@2211' को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष एवं अतिथियों ने हिंदी लेखिका संघ के साहित्य में अवदान की भूरि-भूरि प्रशंसा की और हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित करने तथा साहित्य में लेखिकाओं की भूमिका को रेखांकित करने के लिए संघ को साधुवाद दिया।

विद्या भारती के अखिल भारतीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग आज से

भोपाल। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग 3 से 8 मार्च तक सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय, शारदा विहार भोपाल में आयोजित हो रहा है अभ्यास वर्ग में देशभर से 700 से अधिक पूर्णकालिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। भारत के गौरवशाली अतीत एवं उज्ज्वल भविष्य की झलक दिखलाती प्रदर्शनी का शुभारंभ 3 मार्च को सुबह 10 बजे विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष दूसि रामकृष्ण राव, अखिल भारतीय संगठन मंत्री गोविन्द महंत, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग द्वारा किया जायेगा। 8 मार्च को पूर्णकालिक कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का समापन होगा।

वरिष्ठ मार्गदर्शक, विद्या भारती सुरेश सोनी समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहेगे। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल जी, विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष दूसि रामकृष्ण राव, अखिल भारतीय संगठन मंत्री गोविंद चंद्र महंत, सह संगठन मंत्री यतीन्द्र शर्मा, श्रीराम आरावकर, प्रादेशिक संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी, मोहनलाल गुप्ता, अध्यक्ष सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, शिरोमणि दुबे, प्रादेशिक सचिव सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान पूरे समय उपस्थित रहेगें।

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पूरा आयोजन परिसर इको फ्रेंडली रहेगा, किसी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक, बैनर आदि का उपयोग नहीं किया गया है। तकनीकी रूप से उन्नत परिसरः मुख्य सभागार एवं प्रशिक्षण कक्षों में श्रव्य-दृश्य उपकरणों की स्थापना की गई है।

रमजान शुरू होते ही गाजा में इजरायल ने बरपाया कहर

● अंदर नहीं जाएगा एक भी सामान सभी सहायता पर लगाई रोक

यरुशलम (एजेंसी)। इजरायल ने कहा है कि वह गाजा में भेजी जाने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय सहायता पर रोक लगा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इजरायल अब गाजा में किसी भी तरह का सामान नहीं जाने देगा। यह फैसला ऐसे समय शुरू हुआ है, मुसलमानों का पवित्र धार्मिक महीना रमजान शुरू हुआ है। इसके लिए हमास के संघर्ष विराम को बढ़ाने से इनकार का हवाला दिया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपने बंधकों की रिहाई के बिना संघर्ष विराम की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने साथ ही धमकी दी कि अगर हमास ने संघर्ष के विराम के विस्तार के लिए अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उसे आगे के परिणाम भुगतने होंगे।

पद छोड़ते ही मुश्किल में घिरीं सेबी चीफ माधबी बुच

● धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर का हो गया आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। मार्केट रेगुलेटर सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी पुरी बुच की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और रेगुलेटरी उल्लंघन के मामले में बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने शनिवार को पारित आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी

करेगा और 30 दिनों के भीतर (मामले की) स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है। बुच ने हाल में अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा किया और उनकी जगह तुहीन कांत पांडे को नया सेबी प्रमुख बनाया गया है। अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसके लिए जांच जरूरी है। इसमें कहा गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की निष्क्रियता के कारण सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के प्रावधानों के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। एक मीडिया रिपोर्टर ने इस बारे में शिकायत की थी। उसने कथित अपराधों की जांच की मांग की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, विनियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार शामिल है।

तमिलनाडु और तेलंगाना के बाद अब पंजाब में कोहराम

तीन भाषा फॉर्मूला के खिलाफ खोला मोर्चा

केन्द्र भी ऐक्टिव

नई दिल्ली (एजेंसी)। शिक्षा के अधिकार के तहत योजनाओं के लिए केंद्रीय फंड को रोके रखने और मोदी सरकार द्वारा इन फंड को राज्यों की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन से जोड़ने के खिलाफ तमिलनाडु के विरोध ने भाषा युद्ध को फिर से भड़का दिया है। यह अभी बीजेपी और डीएमके के बीच एक पूर्ण टकराव है। हालांकि, इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि क्या यह अन्य खिलाड़ियों को

पक्ष लेने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे पहले से ही अस्थिर राजनीतिक मिश्रण और भी उग्र हो सकता है। जब सीएम एम के स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आरटीई योजनाओं के लिए 2,512 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की, तो केंद्र ने तमिलनाडु में एनईपी को लागू न करने की ओर इशारा किया। स्टालिन ने कहा कि वह कई करोड़ रुपये के लिए भी हिंदी थोपने के लिए सहमत नहीं होंगे।

युवा नेता की हत्या | **हाथों में मेहंदी...सूटकेस में लाश, हरियाणा में हड़कंप**

कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के हत्यारे की तलाश शुरू

मां का कांग्रेस के ऊपर फूटा गुस्सा, लगाए गंभीर आरोप

चंडीगढ़/रोहतक (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखने के बाद सुर्खियों में आई हिमानी नरवाल की हत्या पर जहां हरियाणा की राजनीति गरमा गई है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हिमानी नरवाल के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हिमानी नरवाल को मौत से पहले खूब पीटा गया। इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस के अनुसार इस मामले की जांच सभी एंगल से की जा रही है। रोहतक के सांपला कस्बा के बस स्टैंड के पास 1 मार्च

की सुबह नीले रंग का लावारिस सूटकेस मिला था। पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो उसमें एक युवती का शव था। बाद में बॉडी के पहचान कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल के तौर पर हुई थी। हिमानी नरवाल की मां सविता ने इंसाफ की मांग की है। मां ने हत्या कर शव सूटकेस में भरकर फेंकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से लोग रंजिश रखते थे। लोगों को लगता था कि ये इतनी छोटी सी उम्र में कैसे इतनी आगे निकल गई। उन्होंने बेटी की हत्या के पीछे पार्टी के किसी सदस्य के ऊपर भी शक जताया है। हिमानी की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दांव पर लगाया था। जब उनसे पूछा गया कि हत्या के पीछे कौन हो सकता है। इस पर हिमानी की मां ने कहा कि मैं तो किसी को जानती नहीं हूं, लेकिन पार्टी के बहुत से लोग मेरे घर आते थे। ऐसे में इसके पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है। सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि वो मेरी बेटी को न्याय दिलवाएं।

एमपी के मुरैना में बारिश के साथ गिरे ओले

● मार्च के पहले सप्ताह में बादलों की धमाचौकड़ी ● लू भी चलेगी, इंदौर-उज्जैन में 3-4 दिन हीट वेव

भोपाल। मध्यप्रदेश में मार्च महीने में तेज गर्मी, लू, बादल और हल्की बारिश वाला मौसम रहेगा। पहले सप्ताह में बादल छाएंगे। वहीं, चौथे सप्ताह में हीट वेव यानी लू चलेगी। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में 3 से 4 दिन लू चल सकती है। 20 मार्च के बाद कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार भी हैं। मौसम विभाग भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश सिंह ने बताया- मार्च में बारिश के सामान्य से कम होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं, तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश में मार्च से ही हीट वेव यानी लू भी चलेगी। इससे पहले शनिवार-रविवार की दरमियानी रात मुरैना के 24 से ज्यादा गांवों में तेज हवाएं चलीं। बारिश के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। सुमावली, दिमनी, अंबाह विधानसभा क्षेत्रों के मृगपुरा, लीला का पुरा, मैथाना, हंसराज का पुरा, बंधा, नायक पुरा और अजीत पुरा समेत कई गांवों में फसलें प्रभावित हुई हैं।

नवंबर-दिसंबर में पड़ी कड़ाके की ठंड

अब बात ठंड की ओवरऑल स्थिति की। इस बार शुरुआती दो महीने यानी नवंबर और दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ी। नवंबर की बात करें तो भोपाल में 36 साल का रिकॉर्ड टूटा। इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में भी पारा सामान्य से 7 डिग्री तक नीचे रहा। पूरे प्रदेश में जनवरी से भी ठंडा दिसंबर रहा। 9 दिन शीतलहर चली। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है जबकि भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर लगाए गए। जनवरी की शुरुआत में 10 से 15 दिन तक कड़ाके की ठंड का दौर रहा, लेकिन फिर तेवर ठंडे हो गए। तीन बार मावठा गिरा लेकिन ओले नहीं गिरे जबकि जनवरी में प्रदेश में ओलावृष्टि का ट्रेंड रहा है। फरवरी में भी मावठा गिरने का ट्रेंड है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दूसरे सप्ताह में ही दिन में गर्मी का असर शुरू हो गया। कई शहर तो ऐसे रहे, जहां पर दिन का पारा 34 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया।

अप्रैल-मई में हीट वेव का असर ज्यादा

बता दें कि मार्च से गर्मी के सीजन की शुरुआत हो जाती है। अगले 4 महीने तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक 15 से 20 दिन तक हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। अप्रैल-मई में हीट वेव का असर ज्यादा हो सकता है। इस कारण 30 से 35 दिन तक गर्म हवा चल सकती है। सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया- 15 मार्च के बाद जब शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचेगा, तब गर्म हवा का असर देखने को मिलेगा। मार्च के पहले दिन शनिवार को बादल छाने की वजह से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार, बादलों की वजह से शनिवार को ग्वालियर में 3.8 डिग्री की गिरावट के बाद पारा 29.8 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, बैतूल, धार, गुना, इंदौर, खंडवा, पचमढ़ी, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, मंडला, नरसिंहपुर, नौगांव, मलाजखंड में भी पारे में गिरावट हुई। मध्यप्रदेश में पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो मार्च महीने में रातें ठंडी और दिन गर्म रहते हैं। बारिश का ट्रेंड भी है। इस बार भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है जबकि रात में 10 से 17 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, मार्च में ग्वालियर में मौसम सबसे ज्यादा बदला हुआ रहता है। यहां रात में पारा 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। जबलपुर में दिन में गर्मी और रात में ठंड रहती है।

एमपी में नर्मदा किनारे नहीं होगा अतिक्रमण

हाईकोर्ट का आदेश-सरकार मास्टर प्लान को सख्ती से लागू करे, 2008 के बाद के निर्माण हटवाए

भोपाल। नर्मदा नदी के किनारे 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सरकार मास्टर प्लान के प्रावधान सख्ती से लागू करे। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश की जीवन रेखा यानि नर्मदा नदी को यह बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार केथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने यह निर्णय दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश का पालन सख्ती से करने का फैसला दिया है, जिसके तहत नर्मदा तटों के 300 मीटर के दायरे से सभी अवैध निर्माण हटाए जाने हैं। हाईकोर्ट ने कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर 2008 के बाद नर्मदा के 300 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में हुए सभी अवैध

निर्माण हटाने का निर्देश अपने ताजा फैसले में दोहराया है। साथ ही राज्य सरकार और सभी नगरीय निकायों को ये भी निर्देश दिया है कि वो पूर्व आदेश के तहत नर्मदा को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठाते रहें। हाईकोर्ट में यह याचिका जबलपुर के एक सामाजिक संगठन नर्मदा मिशन की ओर से दायर की गई थी, जिसमें नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में अवैध निर्माणों से बढ़ रहे प्रदूषण को चुनौती दी गई थी। 2019 से लंबित इस जनहित याचिका पर अब हाईकोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। इससे पहले मई 2024 में जबलपुर के मंगेली घाट पर घनश्याम दास त्यागी नाम के संत ने नर्मदा नदी के 300 मीटर के डायरी में एक आश्रम और गौ-शाला बनाने का मामला सामने आया था। यहां एक संत ने पक्का मकान भी बनाया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि नर्मदा के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता, लिहाजा हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मंगली के पास हुए पक्के निर्माण को हटाया

लोगों को सरकार से भीख मांगने की पड़ गई है आदत

भोपाल। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने राजगढ़ में एक सभा के दौरान लोगों की सरकार से मदद मांगने की आदत पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को सुठालिया में रानी अवंती बाई लोधी की मूर्ति के अनावरण के मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि लोग नेताओं को माला पहनाकर अपनी मांगों का पत्र थमा देते हैं। मंत्री ने इस आदत को गलत बताया और लोगों से देने की भावना विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षण वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ मूर्ति लगाने से समाज नहीं बदलता, बल्कि महापुरुषों के आदर्शों पर चलने से बदलाव आता है। इस कार्यक्रम में कई अन्य नेता और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। प्रहलाद पटेल ने राजगढ़ में रानी अवंती बाई लोधी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों की सरकार से बहुत अधिक मदद की उम्मीद पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोग नेताओं से मिलने जाते हैं और उन्हें माला पहनाकर एक पत्र देते हैं, जिसमें उनकी मांगें लिखी होती हैं। मंत्री ने इसे भीख मांगने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी आदत नहीं है। इसके बजाय लोगों को देने वाला बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोग देने की आदत डालेंगे तो सुखी होंगे और एक अच्छा समाज बना पाएंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि भिखारी जैसा व्यवहार समाज को कमजोर करता है। मुफ्त की चीजों के लालच में पड़ना वीरांगनाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा।

भोपाल में गर्लफ्रेंड से तंग युवक ने किया सुसाइड

पिता का आरोप-लड़की आईफोन मांग रही थी, बात बंद करने की दी थी धमकी

भोपाल। भोपाल के आनंद नगर में 18 साल के युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पिता का आरोप है कि बेटे ने प्रेम प्रसंग के चलते जान दी है। गर्लफ्रेंड उसे परेशान कर रही थी। आए दिन महंगे तोहफे मांगती थी। आईफोन की डिमांड कर रही थी। युवक का शव रविवार सुबह परिजनों ने बाथरूम में फंदे पर लटका देखा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भाई की मौत के बाद बहन ने उसकी गर्लफ्रेंड के घर

हंगामा कर दिया। बहन ने लड़की को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हालांकि पुलिस ने लड़की को छोड़ दिया है। मृतक राज मीणा (18) कारपेंटर था। वह इंडस्ट्रीयल एरिया में फर्नीचर फैक्ट्री में जॉब करता था। राज के पिता ने बताया कि बेटे का रत्नागिरी में रहने वाली एक लड़की से अफेयर था। बेटे ने यह बात घर में भी बता रखी थी, लड़की दूसरी समाज की थी। हमें शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। समझाते थे कि सही उम्र हो जाने पर शादी करा देंगे। राज के पिता ने बताया कि बेटा उसकी भाभी से सभी बातें शेयर करता था। सुसाइड से एक दिन पहले बेटे ने भाभी को बताया था कि गर्लफ्रेंड गिफ्ट में आईफोन मांग रही है। इससे पहले भी वह कई गिफ्ट लड़की को दे चुका था। लड़की उसे प्रताड़ित करने लगी थी। उसके प्रेम का फायदा उठाकर परेशान करती थी। बात नहीं करने की धमकी देकर उसे तंग करती थी। इसी लड़की के कारण मेरे बेटे की जान गई है। राज के पिता का कहना है कि लड़की पर कार्रवाई होना चाहिए। उसकी प्रताड़ना के कारण बेटे की जान गई है। हमने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। वहीं पिपलानी थाने के टीआई अनुराग लाल ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के डिटेल बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

सौरभ शर्मा पर झूठे एफिडेविट को लेकर होगी एफआईआर

अनुकंपा नियुक्ति के लिए बड़े भाई की सरकारी जॉब छिपाई

भोपाल। आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा से लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग पूछताछ कर रहे हैं। अब उसकी नई दिक्कत ग्वालियर से शुरू होने वाली है। दरअसल, सौरभ ने परिवहन विभाग में अनुकंपा नियुक्ति लेते समय शपथ पत्र में बड़े भाई की सरकारी नौकरी की बात छिपाई थी। इस झूठ को लेकर अब परिवहन विभाग शिकायत करने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यालय से हरी झंडी भी मिल गई है। जल्द पुलिस को सौरभ और उसकी मां उमा शर्मा के खिलाफ शिकायत भेजी जा सकती है। सौरभ की नियुक्ति को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू पहले ही लोकायुक्त में शिकायत कर चुके हैं। सौरभ शर्मा दिसंबर 2024 में तब चर्चा में आया था, जब लोकायुक्त, ईडी और आयकर विभाग ने उसके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसी दौरान भोपाल के मेंडोरी में इनोवा कार से 11 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो गोल्ड जब्त किए गए थे। इसका लिंक भी सौरभ से जुड़ा था। इसके बाद सौरभ और उसके सहयोगियों की बेशुमार संपत्ति सामने आई थी। हालांकि, अब तक हुई पूछताछ में सौरभ शर्मा ने यह स्वीकार नहीं किया है कि मेंडोरी में इनोवा कार में मिला सोना और कैश उसका है। ऐसे में आयकर अफसरों के सामने यह परेशानी है कि कैश और गोल्ड के मालिक को सामने लाएं और अपनी जांच रिपोर्ट फाइल करें।

ग्वालियर में 27 दिसंबर को ईडी ने छापेमारी की थी

27 दिसंबर 2024 की सुबह 5 बजे ईडी की टीम ने ग्वालियर के विनय नगर स्थित सौरभ शर्मा के घर पर छापा मारा था। टीम ने दिनभर की कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे, जिन्हें बैग में भरकर ले जाया गया था। छापामार कार्रवाई में ईडी को जानकारी मिली थी कि सौरभ शर्मा की मां ने हाल ही में हाईवे पर करोड़ों की जमीन बेची थी। टीम इस सौदे की सटीक राशि और लेन-देन की प्रक्रिया की जांच कर रही थी। इसके अलावा सिटी सेंटर में उमा शर्मा के नाम पर कई संपत्तियां मिली थीं। इनमें एक व्यवसायिक बिल्डिंग शामिल थी, जहां थंब, टीबीआर और हैश टैग पब संचालित होते हैं।

ग्वालियर में झूठे शपथ पत्र पर नियुक्ति की शिकायत

आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू के मुताबिक, सौरभ ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन में परिवार के सदस्यों के कॉलम में अपने भाई की जानकारी छिपाई थी। सौरभ ने नहीं बताया था कि उसका बड़ा भाई सचिन शर्मा छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी में है। सौरभ की मां उमा शर्मा ने आवेदन में सहमति कॉलम पर हस्ताक्षर किए थे। ग्वालियर के तत्कालीन चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (सीएमएचओ) अनूप कमठान ने इस आवेदन को वेरिफाई किया था। आरटीआई कार्यकर्ता साहू ने इस आवेदन पर सौरभ और तत्कालीन सीएमएचओ सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की थी। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, भोपाल से इजाजत मिल गई है कि ग्वालियर में संबंधित थाने में शिकायत कर कार्रवाई की जाए। इससे पहले आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने दावा किया था कि साल 2015 में सौरभ शर्मा के पिता राकेश कुमार शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद उनकी मां उमा शर्मा ने बड़े बेटे सचिन शर्मा की सरकारी नौकरी की जानकारी छिपाकर झूठा शपथ पत्र पेश किया था। इसके आधार पर सौरभ को 2017 में परिवहन विभाग में तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति मिली थी जबकि उसका बड़ा भाई सचिन पहले से ही छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी कर रहा था। साहू ने सौरभ की नियुक्ति को पूरी तरह गैर-कानूनी बताते हुए विस्तृत जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

एमपी में पहली बार

महाशिवरात्रि पर ड्यूटी से गायब एसीपी के खिलाफ ऐक्शन

अनीता प्रभा शर्मा पर गिरी गाज, ड्यूटी से मिली थीं लापता

भोपाल। राजधानी में महाशिवरात्रि के दिन ड्यूटी से गायब रहने पर एसीपी अनीता प्रभा शर्मा पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीसीपी रियाज इकबाल ने उनसे दो थानों, कोतवाली और तलैया, का कार्यभार वापस ले लिया है। यह घटना भोपाल पुलिस कमिश्नरेट में पहली बार हुई है, जब किसी एसीपी से इस तरह का कार्यभार वापस लिया गया हो। कार्रवाई की वजह शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में एसीपी की अनुपस्थिति बताई जा रही है। भोपाल में महाशिवरात्रि के दिन एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली। शहर में निकलने वाली शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एसीपी अनीता प्रभा शर्मा ड्यूटी से गायब पाई गईं। इस लापरवाही के चलते डीसीपी जोन 3, रियाज इकबाल ने उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके दो थानों का चार्ज वापस ले लिया। अनीता प्रभा शर्मा के पास कोतवाली, तलैया और श्यामला हिल्स, तीन थानों की जिम्मेदारी थी। अब उनके पास सिर्फ श्यामला हिल्स थाने का कार्यभार बचा है।

महाशिवरात्रि की शोभायात्रा के दौरान मिली गायब- महाशिवरात्रि के दिन शोभायात्रा संवेदनशील इलाकों से होकर गुजर रही थी। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण थी। पुलिस अधिकारियों की तैनाती विशेष सतर्कता के साथ की गई थी। इसी दौरान एसीपी अनीता प्रभा शर्मा की गैरहाजिरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जब यह बात उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आई, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला लिया।

इतिहास में पहली बार ऐसी कार्रवाई- डीसीपी रियाज इकबाल ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अनीता प्रभा शर्मा से कोतवाली और तलैया थाने का कार्यभार वापस ले लिया। यह भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी एसीपी के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई की गई हो। इससे पहले किसी भी एसीपी से थाने का कार्यभार वापस नहीं लिया गया था। कोतवाली थाने की जिम्मेदारी अब शाहजहानाबाद के एसीपी निहित उपाध्याय को सौंपी गई है। वहीं, तलैया थाने का कार्यभार हनुमानगंज के एसीपी राकेश बघेल को दिया गया है।

एनीमिया पीड़ित गर्भवती की शिर्डी के डोनर ने बचाई जान

एम्स के डॉक्टरों ने संपर्क कर भोपाल बुलाया, मिली जिंदगी

भोपाल। एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने एक एनीमिया पीड़ित गर्भवती महिला को रेयर ब्लड ग्रुप उपलब्ध कराकर उसकी जान बचाई है। गर्भवती महिला की जान बचाने के लिए न सिर्फ डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन ने तत्परता दिखाई, बल्कि एक रक्तदाता ने 700 किलोमीटर की दूरी तय कर अपना दुर्लभ रक्त देकर महिला को नया जीवनदान दिया। बताया जा रहा है कि महिला को एनीमिया था और वह 40 वीक की प्रेग्नेंसी में थी। एम्स भोपाल में भर्ती गर्भवती महिला की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने तत्काल रक्त चढ़ाने की जरूरत बताई, लेकिन चुनौती यह थी कि महिला का रक्त समूह 'बॉम्बे ब्लड ग्रुप' था, जो अत्यंत दुर्लभ होता है। अस्पताल के ब्लड बैंक में यह उपलब्ध नहीं था। महिला का जीवन संकट में था। डॉक्टरों के पास समय कम था और अगर जल्द ही रक्त नहीं मिलता, तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता था। एम्स भोपाल के निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह को जब यह जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत चिकित्सकों और ब्लड बैंक टीम को सक्रिय कर दिया। ब्लड बैंक में खोजबीन के बाद जब रक्त नहीं मिला, तो समाजसेवी संगठन ब्लड कॉल सेंटर रेड क्रॉस से संपर्क किया गया, जो दुर्लभ रक्त समूहों के रक्तदाताओं की सूची तैयार करने में मदद करता है। इस संगठन के प्रमुख अशोक नायक जो वर्षों से रक्तदान जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, ने मामले को प्राथमिकता से लिया और संभावित रक्तदाताओं की खोज शुरू की। उसी दौरान जानकारी मिली कि शिर्डी में रहने वाले रवींद्र, जो स्वयं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के दुर्लभ रक्तदाता हैं, मदद के लिए आगे आ सकते हैं।

700 किलोमीटर का सफर, जीवन बचाने का संकल्प

समस्या यह थी कि रवींद्र उस समय शिर्डी में थे, जबकि महिला भोपाल में भर्ती थी और उसे तुरंत रक्त की आवश्यकता थी। बिना समय गंवाए, अशोक नायक और एम्स भोपाल प्रशासन की मदद से एक विशेष वाहन की व्यवस्था की गई। रवींद्र ने तत्काल 700 किलोमीटर की यात्रा शुरू की और समय से पहले भोपाल पहुंचने के लिए पूरा प्रयास किया। इस दौरान अस्पताल प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए था और डॉक्टर मरीज की हालत को नियंत्रित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे थे। दूसरी तरफ, रवींद्र भी अपनी यात्रा के दौरान हर घंटे अपनी स्थिति साझा कर रहे थे, ताकि डॉक्टरों को अनुमान रहे कि रक्तदान कब तक संभव होगा। जैसे ही रवींद्र भोपाल पहुंचे, तुरंत मेडिकल जांच के बाद उनका रक्त निकाला गया। फिलहाल महिला अभी स्थिर हालत में है।

तीन-चार महीने से लगातार चेकअप के एम्स आ रही थी

डॉ. रोमेश जैन ने बताया कि, एसोसिएट प्रोफेसर एक प्रेग्नेंट महिला करीब चार महीने से लगाता आ रहीं थीं, हमें इस दौरान पता चला कि महिला का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, जिसके बाद हम पिछले तीन महीने से डिलीवरी के लिए उस ब्लड की तलाश कर रहे थे। वह ब्लड हमें भोपाल में कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो पाया। इस दौरान हमें पता चला कि अशोक नायक जो कि ब्लड डोनेशन सेक्टर में लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारा संपर्क रवींद्र जो कि शिर्डी में रहते हैं उनसे करवाया। वह रात भर में भोपाल पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने ब्लड डोनेट किया। जिसके बाद महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवा पाए। एम्स भोपाल के प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा कि यह घटना हमें याद दिलाती है कि रक्तदान सिर्फ जरूरतमंद के लिए नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। खासतौर पर दुर्लभ रक्त समूह वालों को अपनी जानकारी ब्लड बैंकों में दर्ज करानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और की जान बचाई जा सके।

महिला के पति बोले हम तीन महीने से थे परेशान

महिला के पति कपिल ने बताया कि हम तीन महीने से परेशान हो रहे थे, हमें नहीं लग रहा था कि यह ब्लड कहीं मिलेगा। कई जगहों पर पता करने के बाद निराश ही मिली। मैं रवींद्र जी का आभारी हूं। जो ऐसे समय में वह भोपाल आए। वहीं शिर्डी से आए रवींद्र ने कहा कि बाई कार आया हूं। 28 फरवरी की रात शिर्डी से निकल कर 1 मार्च को भोपाल पहुंचा। मैं लोगों से यही कहूंगा कि रक्त दान हम तीन महीने में करना चाहिए, इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है।

देश भर में 180 लोगों में यह ब्लड ग्रुप

अशोक नायक ने बताया कि हम 16 सालों से लगातार लोगों के लिए ब्लड डोनेशन करवा रहे हैं। इस ब्लड ग्रुप की डिमांड पांच बार आई है। अभी तक हमने पांच बार अरेंज करवाया है। जैसे भाई साहब शिर्डी से आए हैं यह देश में कुल 180 लोगों में पाया गया है। यह दुनिया का सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है। सामान्यतः लोग ए, बी, एबी और ओ ब्लड ग्रुप से परिचित होते हैं, लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप इन सबसे अलग है। इसे 'ह-एच ब्लड ग्रुप' भी कहा जाता है, और यह लाखों में किसी एक व्यक्ति में ही पाया जाता है। इस रक्त समूह की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह न तो ओ ग्रुप से मैच करता है और न ही किसी अन्य रक्त समूह से। इसका मतलब यह है कि यदि किसी मरीज को बॉम्बे ब्लड ग्रुप की जरूरत हो, तो उसे सिर्फ इसी ग्रुप का रक्त चढ़ाया जा सकता है। यही कारण था कि इस गर्भवती महिला की जान बचाना इतना कठिन हो गया था। डॉक्टर्स के अनुसार यह 10 हजार से 1 लाख व्यक्तियों के बीच पाया जाता है। इसकी खोज सबसे पहले साल 1952 में डॉक्टर वाईएम भेंडे ने मुंबई में की थी।

संपादकीय

असमंजस में जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच वाशिंगटन के ओवल हाउस में हुई तल्ख मुलाकात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि जेलेंस्की का रवैया सही नहीं था तो दूसरी तरफ खुद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को माफिया कूटनीति का नाम दिया जा रहा है, जिसका मकसद माफियाओं की तरह अड़ीबाजी करके दूसरे देशों के खनिज संसाधनों पर जबरिया कब्जा करना है। जेलेंस्की और ट्रंप की बहुप्रतीक्षित मुलाकात पर सारी दुनिया की नजरें लगी थीं। उम्मीद थी कि पूर्वी यूरोप में तीन साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध थमेगा और शांति का कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन बातचीत का जो वीडियो सामने आया है और दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच जिस तल्खी से बात हुई है, उससे इस युद्ध ग्रस्त क्षेत्र में जल्द शांति की संभावना कम ही लगती है। हालांकि यह बातचीत विफल होने पर सबसे ज्यादा खुश रूस ही है। क्योंकि वह खनिज संसाधन सम्पन्न यूक्रेन के उत्तरी हिस्से पर पहले ही कब्जा कर चुका है। वैसे भी सैन्य तथा आर्थिक क्षमता के हिसाब से यूक्रेन की ताकत सीमित है, जबकि रूस अभी भी कुछ साल और लड़ सकता है। जाहिर है कि बगैर अमेरिका की मदद के यूक्रेन ज्यादा दिनों तक युद्ध जारी नहीं रख सकता और उसे युद्ध से बाहर निकलने या फिर शांति की स्थिति में स्थायी सुरक्षा की गांरटी चाहिए। क्योंकि भविष्य में रूस बाकी यूक्रेन को निगलने की कोशिश नहीं करेगा, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। केवल उस स्थिति को छोड़कर कि यूक्रेन पूरी तरह अमेरिका के आगे सरेंडर हो जाए या फिर रूस की दादागिरी को स्वीकार कर ले। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध इक्कीसवीं सदी का सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला युद्ध है। इतना ही नहीं, यह आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ लड़ा जाने वाला युद्ध भी है। जिसमें लड़ाई की परंपरागत परिभाषा को भी बदल दिया है। अब तक अमेरिका रूस की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ यूक्रेन की मदद करता रहा है। लेकिन ट्रंप ने इसे सौदेबाजी का रूप दे दिया है और वो रूस से प्रतिद्वंद्विता की जगह उसे दोस्त बनाकर अपना हित साधना चाहते हैं। ट्रंप की इस रीति नीति से समूचा यूरोप भी चिंता में है। उसकी चिंता यह है कि यदि रूस को यूक्रेन में नहीं रोका गया तो बाकी पश्चिमी देश में भी युद्ध और विनाश के लपेटे में आ जाएंगे। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देश बहुत हद अमेरिका पर निर्भर हो गए हैं। फिर चाहे पैसे की बात हो या हथियारों की या फिर तकनीकी कौशल की। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इन देशों के उपनिवेश स्वतंत्र होने के बाद वो पैसा भी बंद हो गया, जो उन्होंने तीन सदियों तक लूट के अपने देशों को अमीर बनाया था। अगर पश्चिमी देशों को अमेरिका की सैनिक व आर्थिक मदद रूक गई तो वो अकेले अपनी दम पर खुद की और यूक्रेन की रक्षा कितनी कर पाएंगे,कहना मुश्किल है। उधर जेलेंस्की के सामने अपने देशवासियों को जवाब देने और अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती भी है। कोई भी इकतरफा समझौता यूक्रेन को विनाश और अपमान की तरफ धकेलेगा। यदि यूक्रेन हथियार नहीं डालता है तो यूरोप के देश तमाम आश्वासनों के बावजूद कब तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, कहना मुश्किल है। क्योंकि वो खुद अमेरिका और परोक्ष रूप से रूस के दबाव में हैं। यह भी सही है कि ट्रंप जिस तरह माफिया स्टाइल में इस मामले को सुलझाना चाहते है, वह शैली समूची दुनिया के लिए नई है। ऐसे में ट्रंप अपने उद्देश्य में कितना सफल होंगे और खुद अमेरिकी उन्हें कहां तक झेलेंगे, यह देखने की बात है।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

भारतीयों का अमेरिका से निर्वासन विवाद

20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ लेने के बाद अमेरिका से अवैध घुसपैठियों को निकाले जाने की खबरें भारत और दुनिया में प्रमुखता से छप रही हैं। यह स्वाभाविक है कि श्री डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकालने की अपनी नीति का शुरू से ही खुला ऐलान किया और इसे कभी भी छिपाया नहीं है। यह उनकी वैचारिक ईमानदारी भी है कि उन्होंने कुछ मतों के नुकसान की चिंता न करते हुये चुनाव अभियान के बीच अपनी बात को साहसपूर्वक कहा है। यद्यपि अमेरिका से भारत और अन्य देशों से अवैधानिक प्रवासियों को निकालने के कार्य उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान भी होते रहे हैं। जो बाइडेन के 4 वर्षीय कार्यकाल के दौरान भी लगभग 16 हजार भारतीय अमेरिका से वापिस भारत भेजे गये थे। परंतु इसकी चर्चा देश व दुनिया के मीडिया में कम हुई। क्योंकि एक तो जो बाइडेन ने इसे अपना नीतिगत मुद्दा नहीं बनाया और न ही कभी ऐसे सार्वजनिक बयान दिये है, वह बगैर बोले निकालते रहे। दूसरा इसलिये भी कि भारत के प्रतिपक्ष के नेताओं का विरोध नीतियों से कम व्यक्ति से ज्यादा होता है। हर बात को वे व्यक्ति के साथ जोड़कर देखते हैं, उनका विरोध न नीतिगत होता है और न निष्पक्ष। और न ही राष्ट्रीय और नैतिक आधार पर होता।

चूंकि वे भारत में श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका में ट्रंप के व्यक्तिगत खिलाफहै अतरू उनका लक्ष्य केवल व्यक्ति होता है। भारत में वैश्वीकरण की औपचारिक शुरुआत केंद्र में कांग्रेस के ही कार्यकाल में ही हुई थी। परंतु उसके मूल अपराधी स्व. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह थे और उसी वैश्वीकरण की नीति को आगे बढ़ाने वाले स्व. अटल बिहारी वाजपेयी उनके लिये श्रद्धा के पात्र हैं, परंतु उसी नीति को आगे ले जाने वाले श्री नरेन्द्र मोदी उनकी नजरों में आर्थिक अपराधों हालांकि उनकी भेदभावपूर्ण प्रतिक्रिया से शायद इसलिये देश प्रभावित नहीं होता।

अब दुनिया में आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी देश अपने देश में बाहर की आबादी को रहने-सहने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार और उनकी पार्टी तो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ को कई दशकों से राजनैतिक मुद्दा बनाये है, हालाँकि वह इन मुद्दों पर वोट तो लेती है, पर करती कुछ नहीं है।

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जब अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किये गये भारतीयों को निकाला जाना शुरू हुआ तो हमारे देश के मीडिया ने और प्रतिपक्षी दलों ने इसे आलोचना का मुद्दा बनाया। संसद में भारी हंगामा हुआ, बहिष्कार हुआ तथा घुसपैठियों को हथकड़ी और जंजीर डालकर अमेरिकी विमान से भारत में पंजाब प्रांत में लाकर अमेरिकी सेना अधिकारियों द्वारा छोड़ने की इस आधार पर

आलोचना हुई कि यह राष्ट्रीय अपमान है। यह बात सही है कि, भारत सरकार को दूरदृष्टि की नीति से पहले ही आवश्यक कदम उठाने थे, तथा बेहतर होता कि भारत के सत्ताधीश पहले ही भारतीय विमान भेजकर भारतीय घुसपैठियों को वापिस ले आते तथा उन्हें भारत में दंडित करते। पर दूसरा भी पक्ष है कि ये अवैध घुसपैठिये अमेरिकी कानून के अनुसार अपराधी हैं, उन्हें देश से निकालने के उनके अमेरिका अपने नियम कायदे हैं। अपने सुरक्षागत नियमों के पालन के आधार पर ही श्री लालकृष्ण आडवाणी जो पूर्व गृहमंत्री थे और स्व. जार्ज फर्नांडीज विदेश मंत्री के जूते मौजे उतरवाकर जांच की थी। शायद यह परंपरा पहले भी रही हो।

अधिकांश भारतीय जो अमेरिका में घुसपैठ होकर गये हैं, वे कनाडा और मैक्सिको की सीमा से घुसपैठ किये गये हैं। मैक्सिको की सीमा पर जाने के लिये कनाडा बीच का स्टेशन जैसा है। देश में कई ऐसी एजेंसियां सक्रिय हैं जो न केवल फर्जी पासपोर्ट बनाने में संलग्न हैं। कई ट्रेवलिंग एजेंसियां भी हैं जो भारत में लोगों से भारी पैसा लेकर अवैध प्रवासी या मानव तस्करी के प्रति आश्वस्त करती हैं और उन्हें कनाडा, मैक्सिको भेज देती हैं। इनके बारे में देश के सत्ता या प्रतिपक्ष ने कभी कोई शिकायत नहीं की, अब जब अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत भेजा गया है तब डिपोर्ट किये लोग इन ट्रेवलिंग एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं। इन एजेंटों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता धारा 313 के तहत कार्यवाही होनी चाहिये। जो लोग इन एजेंटों को भारी पैसा देकर पासपोर्ट बनवाकर गये थे इनके खिलाफभी कार्यवाही होनी चाहिये।

ट्रंप ने तो अमेरिका संशोधित आदेश पर हस्ताक्षर कर दिये थे जिसके अनुसार गैर अमेरिकी नागरिकों के अमेरिका में बच्चों को जन्म देने पर उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं दी जायेगी यह प्रावधान था, हालाँकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभी रोक दिया है, पर यह तय है कि ट्रंप शासन इन घुसपैठियों को चाहे वे भारत के हों या बाहरी अब अमेरिका से बाहर निकालेगा। अमेरिकी प्रशासन ने यह भी बदलाव किया है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद भी अमेरिका में नहीं जा सकेंगे। हालाँकि 26 फरवरी का एक और आदेश श्री ट्रंप ने जारी किया है, जिससे 44 करोड़ रुपये देने वालों को, तत्काल वीजा दिया जायेगा। श्री ट्रंप का कहना है कि अमेरिका योग्य व रोजगार देने वाले को भी नागरिकता देगा। बहरहाल ये विषय भी चर्चा व बहस के हैं।

यह प्रवासी अमेरिका के अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि इन 20 देशों में भी नहीं जा सकेंगे जो अमेरिका की वीजा नीति (वीसा नीति) का पालन करते हैं। भारत से अवैध रूप से गये इन प्रवासियों के विरुद्ध भारत में भी पासपोर्ट अधिनियम 1967, आयकर अधिनियम 1967, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, एमीग्रेसन अधिनियम 1983 के तहत कार्यवाही हो सकती है, यह अलग बात है कि वोट के लालच में केंद्र और राज्य सरकारें यह कार्रवाई करें, या न करें। अमेरिकी कार्रवाई का असर यूरोप के देशों पर भी हुआ है और यूरोप के देश भी अवैध घुसपैठ के खिलाफसक्रिय हुये हैं। ब्रिटेन और जर्मनी ने भी बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों को पकड़कर निकालना शुरू किया है और अभी यूरोप के देशों में होने वाले चुनावों में भी अवैध घुसपैठियों को निकालने का मुद्दा एक प्रमुख और निर्णायक मुद्दा बन रहा है।

ब्रिटिश गृहमंत्री कूपर ने तो घोषणा कर दी है कि अब हम नियमों का सख्ती से पालन करेंगे। जर्मनी के प्रतिपक्ष के नेता फेडरिच मार्टिन ने तो कहा है कि जर्मनी में 20 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं, उन्हें वह सत्ता में आने पर निकालेंगे। भारत को अब यह मान लेना चाहिये कि जो भारतीय अवैध प्रवासी के रूप में देश के बाहर किसी भी देश में गये हैं वे अंतरराष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से कानूनी अपराधी हैं। और उन्हें कभी न कभी वापिस आना होगा।

भारत को स्वतः भी अपनी सीमाओं, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बचाने भारत में आये अवैध घुसपैठियों को निकालना होगा। जो अवैध प्रवासी अमेरिका में गये हैं वे भारतीय और अमेरिकी कानून के हिसाब से अपराधी तो हैं ही बल्कि डंकी रूट से गये हुये ये लोग अमेरिका में बने रहने के लिये जो तर्क दे रहे हैं वे राष्ट्र के सम्मान को गिराने वाले हैं। कुछ आवेदन दे रहे हैं कि वे भाजपा या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इस कारण से भारत में उनकी जान को खतरा है। कुछ कह रहे हैं कि अंतरधर्मी प्रेम शादी के कारण उनकी जान को खतरा है, कुछ लोग अपने परिवार पर भारत में हुये हमले की कहानी गढ़कर अमेरिका में बने रहना चाहते हैं और कुछ लोग भारत के अपने गांव में सामाजिक, धार्मिक दंगों का बहाना बनाकर अमेरिका में शरण चाह रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोगों ने तो अमेरिका में रहने के लिये दिये गये आवेदनों में यह भी लिखा है कि कोरोना काल में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया है, उन पर भारी कर्ज है, भारत सरकार ने मदद नहीं की वे वापिस जायेंगे तो साहूकार उनकी जान ले लेंगे आदि-आदि।

क्या ऐसे लोग अमेरिका में बसने के लिये अपनी मातृभूमि को बदनाम करने को लाचार हैं और किसी दया के पात्र हैं। क्या ये राष्ट्रविरोधी नहीं हैं? ऐसे लोगों की हिमायत करना भी राष्ट्रीय सोच नहीं है। भारत को इन लोगों को देश वापिस लाकर इनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिये। भारत में आये हुये जो घुसपैठिये हैं उन्हें सख्ती के साथ वापिस भेजना चाहिये। यह भारत सरकार और समूची भारतीय राजनीति का राष्ट्रीय दायित्व है और अमेरिका तथा यूरोप में हो रही कार्रवाई भारत के लिये अवसर भी है। श्री नरेन्द्र मोदी जी तो आपदा में अवसर खोजने के विशेषज्ञ हैं। देखें वे, इस आपदा में अवसर खोजते हैं या नहीं?

शिक्षा

प्रियंका सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

अध्यापिकाओं की बढ़ती संख्या महत्वपूर्ण बदलाव

यूडीआईएसई+ 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्कूल शिक्षकों में अब 53.34 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो शिक्षा में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। उच्च शिक्षा में केवल 43 प्रतिशत संकाय महिलाएं हैं, नेतृत्व की भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व और भी कम है। शैक्षणिक जगत में लैंगिक समानता अभी भी जड़ जमाये पूर्वाग्रहों, व्यावसायिक बाधाओं और संस्थागत कठिनाइयों के कारण बाधित है। भारत के शिक्षण कार्यबल में महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता और सामाजिक समानता में आमूलचूल परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षणशास्त्र में लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती दी जाती है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, तथा महिला शिक्षकों द्वारा महिला विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की जाती है। छात्रों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, महिला शिक्षक कक्षा में अधिकाधिक भागीदारी और लिंग-संवेदनशील शिक्षण को प्रोत्साहित करती हैं। यूनेस्को की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं द्वारा संचालित कक्षाओं में समावेशी भागीदारी 20 प्रतिशत अधिक होती है। सामाजिक बाधाओं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करके, महिला शिक्षकों की उपस्थिति लड़कियों के शैक्षिक अवसरों को बढ़ाती है। महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के कारण बिहार की कन्या उत्थान योजना में महिलाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लिंग भूमिकाओं, बाल विवाह और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बातचीत को सामान्य बनाकर, महिला शिक्षक समानता को बढ़ावा देती हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत किशोरियों को महिला शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिला शिक्षकों द्वारा भावनात्मक समर्थन देने की संभावना अधिक होती है, जिससे विद्यार्थियों का कल्याण बेहतर होता है।

उच्च शिक्षा संकाय पदों में महत्वपूर्ण लैंगिक असमानताएं महिला संकाय सदस्यों के कम प्रतिनिधित्व के कारण होती हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, शिक्षण पदों पर पुरुषों की संख्या अधिक होने के बावजूद, उच्च शिक्षा संकाय में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 43 प्रतिशत है। आईआईटी और एनआईटी में महिला संकाय का प्रतिनिधित्व अभी भी 20 प्रतिशत से कम है, जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में लैंगिक असमानताओं को दर्शाता है। अकादमिक नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर तक सीमित है, जहां उनका प्रतिशत तेजी से गिरता है। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 25 प्रतिशत से भी कम पूर्ण प्रोफेसर महिलाएं हैं, जो निर्णयों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। भारत के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में 10 प्रतिशत से भी कम कुलपति महिलाएं हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के कारण, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, जबकि ग्रामीण और उत्तर भारतीय विश्वविद्यालयों में यह कम है। केरल के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में आधे से अधिक प्राध्यापक महिलाएं हैं, जबकि बिहार और राजस्थान में यह प्रतिशत 30 प्रतिशत से भी कम है। नियुक्ति और पदोन्नति में अचेतन पूर्वाग्रहों के कारण महिलाओं के नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने की संभावना कम होती है। अकादमिक महिलाओं को प्रायः मार्गदर्शन और मजबूत व्यावसायिक नेटवर्क का अभाव होता है, जो शोध के अवसरों और कैरियर में उन्नति के लिए आवश्यक है। कई महिलाएं घर के कामकाज की दोहरी जिम्मेदारी के कारण अपने करियर में ब्रेक ले लेती हैं, जिसका असर उनकी उन्नति और शोध कार्य की संभावनाओं पर पड़ता है।

समान कैरियर उन्नति के अवसर सुनिश्चित करना, लिंग कोटा स्थापित करना, चयन समितियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा स्पष्ट पदोन्नति मानकों को लागू करना, शैक्षणिक नियुक्ति समितियों में 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता के द्वारा, जर्मनी का डीएफजी कार्यक्रम अधिक महिलाओं को उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षाविदों में महिलाओं की मेंटरशिप और नेटवर्किंग अवसरों तक पहुंच बढ़ानाः महिला संकाय सदस्यों को वरिष्ठ शिक्षाविदों के साथ जोड़ने के लिए औपचारिक मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करना, वित्तपोषण के अवसरों, अनुसंधान और नेतृत्व विकास पर सलाह देना। केंद्रित मार्गदर्शन और समर्थन नेटवर्क के मूल्य के प्रमाण के रूप में, अमेरिका का 'विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं' कार्यक्रम नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में सहायक रहा है। कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना, परिसर में बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करना, सवेतन मातृत्व अवकाश बढ़ाना, तथा लचीले कार्यकाल पथ को लागू करना, महिला संकाय सदस्यों को मातृत्व के बाद एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार प्रदान करके उनके शोध करियर को जारी रखने में मदद करता है। महिलाओं की प्रशासनिक और शैक्षणिक दृश्यता में सुधार लाने के लिए विशिष्ट वित्तपोषण उपलब्ध कराना तथा उनके लिए नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम चलाना, भारत की 'महिला वैज्ञानिक योजना' महिला शोधकर्ताओं को करियर ब्रेक के बाद वित्त पोषण प्रदान करके शिक्षा जगत में वापस लौटने में मदद करती है। उच्च शिक्षा संकाय में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 43 प्रतिशत है, जो कक्षा के बाहर उनके प्रभाव को सीमित करता है। आईआईटी और आईआईएम में महिला शिक्षकों का प्रतिशत 20 प्रतिशत से भी कम है।

यूजीसी का जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (जीएटीआई) कार्यक्रम महिला संकाय सदस्यों को नेतृत्वकारी पदों पर आसीन होने के लिए प्रोत्साहित करता है। समान वेतन के दिशा-निर्देश स्थापित करें, श्रम कानूनों को अधिक सख्ती से लागू करें तथा अनुबंध शिक्षकों को नियमित करें। निजी शिक्षा में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का सशक्त प्रवर्तन आवश्यक है। परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल, परिवहन विकल्प और शिकायत प्रक्रिया को बेहतर बनाएं। शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा उपायों की स्थापना को निर्भया फंड (2013) द्वारा वित्त पोषित किया गया है। लिंग-संतुलित शिक्षण स्टाफ प्रारंभिक शिक्षा में स्त्रीकरण को कम करेगा और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों को सामान्य बनाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में, फिनलैंड और स्वीडन पुरुषों की भर्ती को आक्रामक रूप से प्रोत्साहित करते हैं। गुमनाम शिकायत निवारण प्रक्रियाएं स्थापित करें, सुनिश्चित करें कि आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) कार्यरत हों, तथा सभी विश्वविद्यालयों में कठोर उत्पीड़न-विरोधी नीतियां लागू करें। यूजीसी के 2023 निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों में आईसीसी आवश्यक है; हालाँकि, अभी भी कार्यान्वयन में खामियाँ हैं, विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण संस्थानों में। शिक्षा जगत में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन कार्यक्रम, समावेशी नियुक्ति प्रथाएं, संस्थागत परिवर्तन और बहुआयामी रणनीति आवश्यक हैं। परिवार-अनुकूल कार्यस्थलों को बढ़ावा देना, पारदर्शी पदोन्नति की गारंटी देना, तथा भेदभाव-विरोधी कानूनों को मजबूत बनाना, उच्च शिक्षा में महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हो सकता है। लिंग-संवेदनशील, योग्यता-आधारित नीतियों की ओर प्रतिमान बदलाव से प्रतिनिधित्व में सुधार होगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

पूंजीवाद साजिशों का खेल, जेलेंस्की और ट्रंप का संवाद

सचिन श्रीवास्तव

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी सीनेटर जेडी वेंस के बीच जो संवाद हुआ, वह सिर्फ दो नेताओं की बहस भर नहीं थी, बल्कि यह वैश्विक राजनीति में साम्राज्यवाद और पूंजीवादी हितों की टकराहट का खुला प्रदर्शन था। इसमें ट्रंप की प्रतिक्रियाएं भी एक बड़े ऐतिहासिक संदर्भ में रखे जाने योग्य हैं। यह पूरा घटनाक्रम अमेरिकी साम्राज्यवाद, सैन्य पूंजीवाद और युद्ध से संचालित अर्थव्यवस्था का ही एक और चरण है।

जेलेंस्कीः साम्राज्यवाद के प्यादे का संकट- वोलोदिमीर जेलेंस्की को यूक्रेन में पश्चिमी देशों द्वारा 'लोकतंत्र का चेहरा' बताकर स्थापित किया गया। असल में, वे अमेरिकी और यूरोपीय सैन्य-औद्योगिक हितों के लिए काम करने वाले एक प्रॉक्सी नेता हैं। 2014 में हुए मैदान विद्रोह और उसके बाद रूस-यूक्रेन संघर्ष को देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यूक्रेन को पश्चिमी ताकतों ने रूस के खिलाफ़ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। जेलेंस्की का सत्ता में आना भी इसी साम्राज्यवादी योजना का हिस्सा था।

यह लड़ाई यूक्रेनी जनता की नहीं है, बल्कि पूंजीपति वर्ग की भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की उपज है। जेलेंस्की जिस 'लोकतंत्र और संप्रभुता' की बात करते हैं, वह असल में अमेरिकी और नाटो समर्थित सैन्य गठजोड़ का विस्तार भर है। यूक्रेन को लगातार हथियारों से भरकर अमेरिका ने इसे एक रणक्षेत्र बना दिया है, जहां असल कीमत वहाँ के श्रमिकों, किसानों और आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है।

जेडी वेंसः अमेरिकी साम्राज्यवाद में दरारें?- सीनेटर जेडी वेंस का यह कहना कि 'यूक्रेन को दी जाने वाली मदद से अमेरिकी करदाताओं का नुकसान हो रहा है,' एक दिलचस्प मोड़ है। यह ट्रंपवादी राजनीति की ओर झुकाव रखने वाले रिपब्लिकनों की साम्राज्यवादी रणनीति में बदलाव को दिखाता है। अमेरिकी सैन्य-औद्योगिक तंत्र की प्राथमिकता अब चीन पर केंद्रित हो रही है, इसलिए रूस के खिलाफ़ यूक्रेन में अनावश्यक संसाधन लगाना एक मुद्दा बन रहा है।

हालांकि, जेडी वेंस का यह विरोध अमेरिकी जनता के हितों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी पूंजीपतियों के नीतिगत बदलाव का संकेत है। जब तक यूक्रेन युद्ध से अमेरिकी हथियार कंपनियों और ऊर्जा लॉबी को फायदा हो रहा था, तब तक वेंस और उनके साथी चुप थे। अब जब पूंजीवादी हितों को दिशा बदलनी है, तो यह नया विमर्श खड़ा किया जा रहा है कि 'हमें पहले अमेरिका की चिंता करनी चाहिए।' यह वही रणनीति है, जो ट्रंप 2016 से अपनाते आए हैं- 'अमेरिका फर्स्ट'।

ट्रंपः पूंजीवाद का एक और चेहरा- डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान और पारंपरिक साम्राज्यवादी धड़े से अलग एक 'पॉपुलिस्ट' नेता के रूप में देखा जाता है, लेकिन असल में वे भी पूंजीवाद के ही एक और चेहरे हैं। ट्रंप का यह कहना कि 'अगर वे सत्ता में आते हैं, तो रूस-यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में खत्म कर देंगे,' एक भ्रामक बयान है। इसका असली मतलब यह है कि अमेरिका को यूरोपीय युद्धों में नहीं, बल्कि एशिया (चीन) और घरेलू औद्योगिक पुनर्गठन में निवेश करना चाहिए।

असल में, ट्रंप और बाइडन की नीतियों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही अमेरिकी पूंजीवाद को बनाए रखने के लिए अलग-अलग रणनीतियां अपनाते हैं। बाइडन नाटो विस्तार और सैन्य गठबंधनों के माध्यम से अमेरिका के प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि ट्रंप इसे आंतरिक पुनर्गठन और 'इकोनॉमिक नेशनलिज़्म' के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं कि पूंजीवाद अपने ही अंतर्विरोधों से ग्रस्त है। साम्राज्यवादी युद्ध इन अंतर्विरोधों को हल करने का तरीका होते हैं। लेनिन ने अपनी किताब 'इंपेरियलिज्मः द हाईएस्ट स्टेज ऑफ केपिटलिज्म' में यह स्पष्ट किया है कि पूंजीवाद का अंतिम चरण साम्राज्यवाद ही होता है, जहां युद्ध पूंजी संचय का एक आवश्यक साधन बन जाता है।

यूक्रेन युद्ध इसका एक सटीक उदाहरण है। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप की हथियार कंपनियां इस संघर्ष से अरबों डॉलर कमा रही हैं, जबकि आम यूक्रेनी मजदूर और रूसी सैनिक अपनी जानें गंवा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और खाद्यान्न संकट भी इसी युद्ध का नतीजा हैं। जेलेंस्की पश्चिमी साम्राज्यवाद का मोहरा हैं, जो 'लोकतंत्र' के नाम पर यूक्रेन को नष्ट कर रहे हैं। जेडी वेंस और ट्रंप जैसे नेता अमेरिकी पूंजीवाद के नए स्वरूप की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं पूंजीपतियों के हितों से ही संचालित होती हैं। असली समस्या यह है कि युद्ध और पूंजीवाद का रिश्ता अटूट है- जब तक पूंजीवाद रहेगा, युद्ध इसके अस्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा रहेगा। इसलिए, अगर किसी को वास्तव में युद्धों को रोकना है और विश्व शांति स्थापित करनी है, तो उसे पूंजीवाद के मूल ढांचे को बदलने की दिशा में सोचना होगा। केवल सत्ता बदलने या 'अमेरिका फर्स्ट' जैसी नीतियों से कुछ भी नहीं बदलेगा। सवाल यह है कि हम कब तक पूंजीवादी झूठ और साम्राज्यवादी छल को नज़रअंदाज करते रहेंगे?

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सुरेश सौरभ

लेखक व्यंग्यकार हैं।

नेता जी ताजिंदगी आप लोगों के शुक्रगुजार रहेंगे

एक नेताजी ने अपनी फेसबुक वॉल पर रात में लिखा-'जुकाम हो गया' फौरन कमेंट की बरसात शुरु हुई।

- श्री मान जी आप को आयुर्वेदिक काढ़ा लेना चाहिए। जरा भी लापरवाही उचित नहीं।

- भीषण सर्दी का मौसम है। ऐसे मौसम में भी ज्यादातर आप का समय समाजसेवा में जाता है। कृपया खुद का ख्याल रखें।

- वैसे किसी काढ़ा-वाढ़ा के चक्कर में न पड़े तो बेहतर है। मैंने तमाम काढ़े पीकर देख लिये,सब ववाल है। किसी अच्छे डॉक्टर को जरूर दिखाएँ। कफ-पित्त-वात यह त्रिदोष मानव जाति में विकार पैदा करने की मुख्य जड़े हैं, यही विकार सेहत को डाउन करते हैं। सेहत डाउन तो समझो सारे काम-धाम डाउन। आप अपना पूरा ख्याल रखें। अगर आप डाउन पड़ गये तो समाज का, देश का, भला कैसे होगा। आप जैसे नेता-मंत्री देश के भाग्य विधाता हैं। अगर हमारा भाग्य विधाता ही अस्वस्थ हो जायेगा, तो देश का, समाज का कौन पुरसाहाल होगा?

- वैसे परसों ही मैने आप के साथ मंच साझा किया था, यह पिक देखिए कैसे आप गरीबों को कंबल बाँटते हुए खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। मचल रहे हैं, फिर आज आप कैसे अस्वस्थ पड़ गये, यह मेरे लिए, समस्त देश वासियों के लिए घोर चिंता का विषय है।

- मुझे लगता है, यह मौसमी जुकाम है। आप को होम्योपैथ की शरण में जाना चाहिए। ऐलोपैथिक दवाएं सीने में जकड़न पैदा कर देती हैं। रात को सोते समय नाक से घर्र घर्र की बेसुरी आवाजें निकलती हैं, जिससे आप के घर के लोग और पड़ोसी जन पूरी रात परेशान हो जाएंगे, सो नहीं पाएंगे। इसलिए होम्योपैथ

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलीसीटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

हिंदू विवाह अधिनियम में 'जैन' के सम्मिलित होने पर सवाल

हिंदू धर्म में वेद उपनिषद एवं स्मृति जैसे ग्रंथों की मान्यता है। वही जैन धर्म का 'आगाम' जैसे अनेक पृथक पवित्र ग्रंथ है। हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है, जैन धर्म में यह मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में जैन विवाह को हिंदू विवाह की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। लेकिन, धारा 2 (1) हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जैन धर्म उक्त अधिनियम के अंतर्गत जैन धर्म द्वारा संपन्न विवाह विधिवत एवं मान्य है। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान कहते हैं कि इसमें केवल हिंदू धर्म के अलावा सिख, बौद्ध एवं जैन समाज भी उक्त अधिनियम के अधीन है।

हाल ही में कुटुंब न्यायालय के एक आदेश ने सबको चौंका दिया है। यह कहना अधिक सही होगा कि विधि के जानकारों को भी स्तंभित किया। सामान्यतः कानून की ऐसी विवेचना की कल्पना भी संभव नहीं थी। कुटुंब न्यायालय ने आपसी सहमति से तलाक के एक मामले में यह ठहराया कि, जैन धर्म मानने वालों को केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र द्वारा अल्पसंख्यक ठहराया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि जैन अल्पसंख्यक होकर एक बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इस कारण इन पर हिन्दू विवाह अधिनियम प्रावधान लागू नहीं होंगे। कुटुंब न्यायालय के समक्ष यह याचिका याचिकाकर्ता पति-पत्नी द्वारा आपसी सहमति से तलाक प्राप्त करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के अंतर्गत प्रस्तुत की थी। कुटुंब न्यायालय ने विचार के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि उक्त आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। कुटुंब न्यायालय ने कहा कि उक्त दंपत्ति धारा 7 कुटुंब न्यायालय में उपयुक्त आवेदन लगा सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत धारा 2 (क) के प्रावधानों के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो एवं धारा 2 (ख) के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति को धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो। धारा 2 (1) हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान यह कहते हैं कि उक्त अधिनियम केवल हिंदू धर्म के अनुयायी या सिख, बौद्ध एवं जैन समाज भी उक्त अधिनियम के अधीन है।

इन प्रावधानों को देखते हुए कुटुंब न्यायालय का यह निष्कर्ष सही प्रतीत नहीं होता है कि जैन हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। लेकिन, कुटुंब न्यायालय ने अपने इस फैसले में यह ठहराया है कि वर्ष 2014 अल्पसंख्यक मंत्रालय के एक अधिसूचना के द्वारा जैन धर्मावलंबियों को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया जा चुका है। उक्त अधिसूचना को माना जाए तो प्रश्न उपस्थित होता है, कि क्या एक अल्पसंख्यक समाज, हिंदू समाज का जो कि बहुमुखी है, का हिस्सा हो सकता है? अपने विचार में न्यायाधीश ने कई वेद पुराणों का उल्लेख भी

किया। इनमें यह उल्लेख है कि हिंदू धर्म में वेद उपनिषद एवं स्मृति जैसे ग्रंथों की मान्यता है। वही जैन धर्म का आगाम जैसे अनेक पृथक पवित्र ग्रंथ है। हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। वहीं दूसरी ओर जैन धर्म में यह मान्यता नहीं है। ऐसी स्थिति में जैन विवाह को हिंदू विवाह की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इस स्थिति में जैन धर्म एवं अन्य समुदायों के लोग हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत एवं अधीन नहीं माने जा सकते।

यहां तक कि उक्त न्यायालय के समक्ष तर्क के समय इस आशय का भी तर्क किया गया कि जैन धर्म के अनुयायी द्वारा भी विवाह के समय हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 में उल्लेखित सप्तपदी संस्कार का पालन किया जाता है। इस कारण ऐसी अनुयायी को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत भी अनुतोष पाने का अधिकार है। कुटुंब न्यायालय ने इस संबंध में 10वीं शताब्दी में आचार्य श्री वर्धमान सूरीश्वरजी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ आचार्य दिनकर ग्रंथ का उल्लेख किया है। इसके 14वें खंड में जैन मान्यताओं के अनुसार विवाह के लिए किए जाने वाले सम्पूर्ण अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार जैन विवाह विधि में स्थापना विधि, आत्मरक्षा, मंत्रस्नान, क्षेत्रपाल पूजा, मनधोड़ बंधन, अरहत पूजन, सिद्ध पूजन, गांधार पूजन, शास्त्र पूजन, चौबीस यक्ष यक्षिणी पूजन, दस दिगपाल पूजन, सोलह विद्यादेवी पूजन, बार राशि पूजन, नवग्रह पूजन, सत्यविश नक्षत्र पूजन, चोरण प्रतिष्ठा, विधि प्रतिष्ठा, हस्तमिलाप, प्रदक्षिणा (चार बार), वरमाला, अभिसिंचन, सात प्रतिज्ञा, आरती एवं क्षमायाचना किए जाने का उल्लेख किया गया। जिससे स्पष्ट है कि जैन धर्म में उल्लेखित विवाह विधि हिंदू धर्म में उल्लेखित विवाह विधि से भिन्न है।

धारा 2 (1) हिन्दू विवाह अधिनियम के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि जैन धर्म उक्त अधिनियम के अंतर्गत जैन धर्म द्वारा संपन्न विवाह विधिवत एवं मान्य है। परंतु, इस मामले में कुटुंब न्यायालय द्वारा यह भी ठहराया गया कि उक्त जैन धर्म को अधिसूचना 27 जनवरी 2014 द्वारा यह अधिसूचित कर दिया गया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अंतर्गत जैन समुदाय को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उन्हें धारा 2 खंड (ग) में शामिल किया जाता है। यह बात ध्यान रखना होगी कि उक्त अधिसूचना के अंतर्गत केवल राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के लिए ही जैन समाज को अल्पसंख्यक माना गया है।

साथ ही उक्त अधिसूचना के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों में कोई बदलाव प्रभावशील नहीं हुआ और न कोई अधिसूचना उक्त बदलाव के संदर्भ में जारी हुई। अतः उक्त अधिसूचना 27 जनवरी 2014 का किसी प्रकार का बदलाव हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों पर नहीं पड़ना चाहिए।

गौरतलब है कि उक्त फैसले पर एक याचिका पहले ही उच्च न्यायालय की युगल खंठपीठ के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। उक्त मामले में युगल पीठ के समक्ष यह बात रखी गई कि उक्त फैसले के आलोक में 28 याचिकाएं उक्त कुटुंब न्यायालय द्वारा खारिज की गई। अतः उच्च न्यायालय की युगल पीठ द्वारा कुटुंब न्यायालय को यह निर्देश दिए गए कि अगली सुनवाई तक कुटुंब न्यायालय अपने समक्ष विचाराधीन कोई अन्य याचिका अपने इस आदेश के प्रकाश में खारिज न करें। यह पहली बार नहीं है, जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने भी बाल पाटिल विरूद्ध भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी, न्यायमूर्ति डीएम धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति पीके बालासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि संविधान निर्माण के समय सिख और जैन जैसे तथाकथित अल्पसंख्यक समुदायों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं माना गया था।

वास्तव में, सिखों और जैनों को हमेशा व्यापक हिंदू समुदाय का हिस्सा माना गया। इसमें विभिन्न संप्रदाय, उप-संप्रदाय, विश्वास, पूजा की विधियां और धार्मिक दर्शन शामिल हैं। संविधान के प्रावधानों और देश के विभाजन के बाद संविधान के अस्तित्व में आने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना संवैधानिक लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष संरचना के लिए एक गंभीर आघात होगा। हमें अपने देश को बहुराष्ट्रीयता पर आधारित एक धार्मिक राज्य के समान बनने से बचाना चाहिए। हमारे धर्मनिरपेक्षता के विचार को संक्षेप में कहें तो, इसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। साथ ही, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से आग्रह किया कि वह सभी धार्मिक समूहों को संवैधानिक दृष्टिकोण, सिद्धांतों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में बनाए रखने के लिए अपनी गतिविधियों को तेज करे।

पीठ की ओर से अपने निर्णय में यह कहा गया कि संविधान ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि राज्य सभी धर्मों और धार्मिक समूहों के साथ समान व्यवहार करेगा और उन्हें समान सम्मान देगा। लेकिन, उनके व्यक्तिगत अधिकारों, धर्म, आस्था और पूजा में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम और अन्य पूर्व और उत्तर-संविधान काल के विभिन्न संहिताबद्ध प्रथागत कानूनों में हिंदू की परिभाषा में हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय, उप-संप्रदाय, सिख और जैन शामिल हैं। अब यह देखना दिलचस्प यह होगा कि इन मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है।

विश्व वन्यजीव दिवस

डॉ. रमेश ठाकुर

लुप्तप्राय होते वन्यजीवों को बचाने की चुनौती बरकरार?

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), भारत सरकार! संसार के जंगल आग की लपटों में घिरे हैं जिनमें बेजुबान जानवर बे-हिसाब जल रहे हैं। वन्यजीवों के जीवन को इंसानी हरकतें भी रौंद रही हैं। ऐसे में वन्यजीवों के जीवन को बचने की भला कल्पना कैसे की जा सकती हैं। विश्व का कोई ऐसा जंगल नहीं, जो पूरी तरह से वन्यजीवों के लिए मौजूदा वक्त में सेफ हो? तकरीबन जंगलों में आग लगने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। अमेजन के जंगलों से लेकर उत्तराखंड के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। इन विकट परिस्थितियों के बीच सालाना 3 मार्च को 'विश्व वन्यजीव दिवस' मनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, ताकि उत्पन्न स्थितियों पर विश्व समुदाय मिलकर कुछ विमर्श करे। ये दिन इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इसी दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के जीवन को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर किए गए थे। सभी को मिलकर समीक्षा करने की जरूरत है कि वह संकल्प कितना आगे बढ़ा? जो वन्यजीवों को बचाने के लिए सामूहिक रूप से हुआ था? संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 'विश्व वन्यजीव दिवस' वन्यजीवों को समर्पित एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है। पर, इसका अमल कितना हुआ, उस पर बिना देर किए मंथन की जरूरत है।

निश्चित रूप से वन्यजीव इंसानी जाति के लिए किसी खूबसूरत प्रकृति उपहार से कम नहीं हैं। अमूल्य धरोहरों से भी बढ़कर माने? पर, अफसोस वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियां दिनोंदिन लुप्तप्राय हो रही हैं। एकाध नहीं, बल्कि संसार की हजारों वन्य प्रजातियां मिट गईं। जंगली बेजुबान जानवरों की संख्या विलुप्त होने से कैसे रोकें? वन्यजीवों का संरक्षण किस तरह हो? उन्हीं को ध्यान में रखकर सालाना 'विश्व वन्यजीव दिवस' मनाया जाता है। विभिन्न किस्म के दुर्लभ वन्यजीवों की आबादी सबसे अधिक अमेजन के जंगलों में पाई जाती है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से वहां धधकती आग ने 20 फीसदी वन्यजीवों की संख्याओं को कम कर दिया। ग्लोबल स्तर के प्रस्तुत आंकड़ों में बेजुबान जंगली जानवरों की आबादी 20 फीसदी घट चुकी हैं। ये आंकड़े निश्चितही रोंगटे खड़े करती हैं। समय रहते अगर इस विकराल स्थिति पर गौर नहीं हुआ, तो आने वाली पीढ़िया वन्यजीवों के दीदार से महरूम हो जाएंगी।

कमोबेश, ऐसे ही हालात भारत में भी बने हुए हैं। इसलिए, सालाना भारत में 4 सितंबर को 'राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस' वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ व वन्यजीव संरक्षणवादी 'स्टीव इरविन' की स्मृति को सम्मानित करने के तौर पर मनाया जाता है। भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक करीब 48.5 फीसदी वन्य प्रजातियों की आबादी में कमी आ चुकी है। इन प्रजातियों की कुल संख्या 16,150 है जिनमें पक्षियों की 5412 प्रजातियां, उभयचरों की 3135, मछलियों की 2631 प्रजातियां, स्तनधारियों की 1885 और कीटों की 1622 प्रजातियां शामिल हैं। जबकि, सरीसृपों की 1465 प्रजातियों में विलुप्तता के कगार पर हैं।

बहरहाल, वन्यजीवों के घटने के पीछे दो मुख्य कारण प्रमुख हैं। अव्वल, वनों का तेजी से कटना। दूसरा, उनके भोजन की उपलब्धता में कमी आना? जिस कारण उनका वनों से बाहर आना और शिकारियों द्वारा शिकार हो जाना? उचित आवास का न होना, अत्यधिक वन संपदा का दोहन, जंगलों में बढ़ता प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की मार भी जंगली जीव झेल रहे हैं। लुप्तप्राय जानवरों और उनके संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों में और तेजी लाना ही आज के खास दिन का मकसद है। वन्य जीव प्रजातियों के महत्व और उनकी रक्षा-सुरक्षा के लिए सभी को भागीदार होना होगा। आज पशुओं की सुंदरता और उनके मूल्यों को पहचानने का दिन है। कार्यक्रमों के जरिए जनमानस को ये भी याद दिलाना होता है कि मानव जीवन में वन प्रजातियों की क्या भूमिकाएं होती हैं। लाख कोशिशों के बाद भी वन्यजीवों पर मानवीय गतिविधियां नहीं रुक रही।

तस्कर चुनचुन कर जंगली जानवरों को निशाना बना रहे हैं। क्योंकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जंगली जानवरों की खाल, दांत व अन्य अंगों की भारी डिमांड होने लगी है। ग्राहक तस्करों को मुंह मांगी कीमत देते हैं जिस कारण तस्कर वन्य जीवों का शिकार करने पर आमादा रहते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस का उद्देश्य व्यक्तिगत प्रयासों से लेकर वैश्विक पहलों तक, वन्यजीवों के संरक्षण में मदद करने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करना होता है। ये दिन हमें अपने प्राकृतिक परिवेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना और चिड़ियाघरों, अभयारण्यों और वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित संगठनों के काम का समर्थन भी आज का दिन करता है। 'विश्व वन्यजीव दिवस' जंगली जानवरों की रक्षा के लिए लोगों को आह्वान करता है कि भावी पीढ़ियां पृथ्वी की जैव विविधता का आनंद ले सकें, इसलिए वन्य जीवों को किसी भी सूरत में संरक्षित करना होगा?

जयंती पर विशेष

चेतनादित्य आलोक

लेखक रांची निवासी पत्रकार हैं।

भारतीय उद्योगों के पिता जमशेद जी टाटा

नमक से लेकर ट्रक तक सबकुछ बनाने वाला लगभग 150 साल पुराना भारत का दिग्गज औद्योगिक घराना 'टाटा' एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह है। सच कहा जाए तो 'टाटा' एक ऐसा ब्रांड है, जिस पर भारतीय लोगों का आरंभ से ही बेहद गहरा विश्वास रहा है और आज भी पूर्ववत कायम है। गौरतलब है कि किसी भी कंपनी के लिए इस प्रकार का नाम और मुकाम हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता। यह उपलब्धि एक दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसके लिए अपने जीवन को बहुत तपाना पड़ता है... सपनों की नैया डुबोनी पड़ती है... भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है और मन को कदम-कदम पर मारना पड़ता है। जाहिर है कि देश के अग्रणी उद्यमी समूहों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा को भी अपनी कंपनी को स्थापित करने और उसे वर्तमान मुकाम तक ले जाने में काफी परिश्रम करना पड़ा था। बता दें कि जमशेद जी टाटा के जीवन में परिस्थितियां कभी भी उद्योग और कारोबार के लिए अनुकूल नहीं थीं, लेकिन उन्होंने जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं और बाधाओं से आगे जाकर सोचा और अपने लक्ष्यों के प्रति सजग एवं दृढ़ होकर ऐसे-ऐसे कार्य करने तथा ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करने का संकल्प लिया, जो किसी के लिए भी बेहद कठिन कार्य हो सकता था।

भारतीय उद्योगों के पिता- दरअसल, जमशेद जी ने उस दौर में औद्योगिक विकास का रास्ता चुना, जब ऐसा माना जाता था कि भारत में केवल अंग्रेज ही उद्योगों को कुशलतापूर्वक स्थापित एवं संचालन कर सकते थे। इसलिए उन प्रतिकूल परिस्थितियों में अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई अड़चनों एवं उनकी प्रताड़नाओं को सहन करते हुए भी टाटा कंपनी को स्थापित करने एवं शिखर तक ले जाने के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों एवं अमूल्य योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता, जिसके कारण बाद में भारतीय उद्योग जगत को भी एक नई पहचान और ऊंचाई मिली। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जमशेद जी के असाधारण अवदानों के कारण ही भारतीय उद्योग जगत् को दुनिया भर में एक नई पहचान और नया नाम एवं मुकाम मिला। यही कारण है कि जमशेद जी टाटा को 'भारतीय उद्योगों का पिता' कहा जाता है।

पारिवारिक पेशे को नकारा- दक्षिणी गुजरात के नवसारी में 03 मार्च 1839 को एक पारसी परिवार में जन्मे जमशेद जी का पूरा नाम जमशेद जी नुसीरवान जी टाटा था। उनके पिता का नाम नुसीरवान जी और माता का नाम जीवन बाई टाटा था। गौरतलब है कि जमशेद जी का परिवार पेशे से पुजारी था। उनके पिता नुसीरवान जी टाटा भी पुजारी का ही कार्य करते थे, किंतु एक समय के बाद उन्होंने अपने खानदानी पेशे को नकारते हुए व्यवसाय का रास्ता अपना लिया था। इस प्रकार, नुसीरवान जी टाटा अपने परिवार में पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले अपना व्यवसाय आरंभ किया था, और शायद इसका ही प्रभाव उनके बेटे जमशेद जी टाटा पर भी पड़ा। जमशेद जी महज 14 वर्ष की आयु में पिता के साथ मुंबई आ गए, जहां नुसीरवानजी ने व्यवसाय शुरू किया तो उन्होंने भी अपने पिता का साथ देना शुरू कर दिया था। 17 वर्ष की आयु में जमशेद जी ने मुंबई के एलफिंसटन कॉलेज में नाम लिखाया और 1858 में ग्रीन स्कॉलर यानी स्नातक स्तर की डिग्री प्राप्त कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे अपने पिता के व्यवसाय में पूरी तरह से लग गए। उसी दौरान हीरा बाई दबू नामक महिला से उनका विवाह करा दिया गया।

21 हजार से शुरू किया व्यापार- जमशेद जी ने 29 वर्ष की आयु तक अपने पिता की कंपनी में काम किया और वर्ष 1868 में महज 21 हजार रुपए के निवेश से अपना अलग एक व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित किया। उसके बाद 1869 में जमशेद जी ने एक दिवालिया तेल

मिल को खरीद कर उसे कॉटन मिल यानी रुई के कारखाने में परिवर्तित कर दिया, जिसका नाम उन्होंने 'एलेक्जेंडर मिल' रखा। दो वर्ष तक उस मिल को चलाने के बाद उन्होंने उसे बेचकर अच्छा लाभ कमाया। मिल बेचकर उन्होंने जो पूंजी कमाई, उससे 1874 में नागपुर में एक कॉटन मिल की स्थापना की। एक जनवरी 1877 को जब क्वीन विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी 'इम्प्रेस' घोषित किया गया तो जमशेद जी ने उस मिल का नाम भी इम्प्रेस रख दिया। दरअसल, वह इम्प्रेस मिल जमशेद जी टाटा के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुई, जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया।

लाखों लोगों को दिया रोजगार- जमशेद जी ने अपने जीवन में देश के अलग-अलग हिस्सों में 04 बड़ी परियोजनाएं लगाईं। इनमें थी एक स्टील कंपनी, एक वर्ल्ड क्लास होटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक जलविद्युत परियोजना। इनके पीछे जमशेद जी की दृष्टि भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने की थी। हालांकि उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही परियोजना पूरी हो सकी, होटल ताज, जो एक वर्ल्ड क्लास होटल था। बाद में उनके सपने को टाटा की आने वाली पीढ़ियों ने पूरा किया। इन्हीं 04 परियोजनाओं के कारण बाद में भारत भर में टाटा ग्रुप की कारोबारी हैसियत बन सकी। ऐसा कहा जाता है कि जमशेद जी की इन्हीं सफलताओं ने पहली बार भारतवर्ष को औद्योगिक तौर पर एक आत्मनिर्भर देश बनने का स्वप्न दिया था। वे भारतीय उद्योग जगत् के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहे हैं और निश्चय ही आगे भी बने रहेंगे। बता दें कि भले ही उन्होंने अपनी औद्योगिक यात्रा की शुरूआत शून्य से की थी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित औद्योगिक घराने ने अब तक न केवल लाखों भारतीयों को रोजगार देने का कार्य किया है, बल्कि इसने उच्च नैतिक मानदंड को भी हमेशा बनाए रखा रखा है।

इसलिए होटल खड़ा किया- 1889 में, जब जमशेद जी का नाम देश के बड़े कपड़ा व्यापारियों में लिया जाने लगा था और स्टील कंपनी खोलने की घोषणा भी कर चुके थे, तब उन्होंने अचानक बॉम्बे (अब मुंबई) में एक आलीशान होटल बनाने की घोषणा करके सबको चैंका दिया था। दरअसल, जमशेद जी टाटा अपने एक व्यापारी मित्र के निमंत्रण पर मुंबई के काला घोड़ा इलाके में एक होटल में ज्योंहि पहुंचे, उन्हें यह कहकर होटल के गेट से ही वापस भेज दिया गया कि यहां सिर्फ 'गोरे' लोग यानी अंग्रेजों को ही एंट्री मिलती है। जमशेद जी टाटा उस समय तो अपमान का घूंट पीकर रह गए, लेकिन उन्होंने उसी क्षण यह प्रण कर लिया था कि कि वे एक ऐसा होटल बनाएंगे, जहां भारतीय और विदेशी सभी बिना रोक-टोक के आ-जा सकेंगे। 16 दिसंबर 1902 को होटल ताज को पहली बार मेहमानों के लिए खोला गया। तब पहली बार 17 मेहमानों ने ताज में कदम रखा। यह देश का पहला होटल था, जिसे बार (हार्बर बार) और दिन भर चलने वाले रेस्त्रां का लाइसेंस प्राप्त था। साथ ही, यह पहला होटल था, जहां बिजली थी। इतना ही नहीं, पहली बार ताज होटल में ही इंटरनेशनल स्तर का डिस्कोथेक भी लगाया गया था। जहां जर्मन एलीवेटर्स लगाए गए थे। यह पहला होटल था, जहां अंग्रेज बटलर्स हायर किए गए थे।

कर्मचारी कल्याण का कार्य किया- जमशेद जी ने इम्प्रेस मिल में कर्मचारियों को भत्ते देने शुरू किए, जिससे टाटा ग्रुप की पहचान 'इम्प्लाइ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन' के तौर पर बनी। जमशेद जी ने अपनी जिंदगी (1880-1904) में टाटा ग्रुप को खड़ा करने का भरपूर प्रयास किया। शैक्षणिक संगठन से लेकर स्टील और मोटर उद्योग स्थापित किए। देखा जाए तो आज टाटा ग्रुप 29 कंपनियों का संचालन करता है, जिनमें टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाइटन, तनिष्क, वोल्टास, टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंट, टाटा एलेक्सी आदि कंपनियां शामिल हैं।

भाषा को लेकर कब थमेगी यह ओछी राजनीति?

सामयिक चिंतन

विनोद नागर
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, और साहित्यकार हैं)

देश की राजधानी दिल्ली में अभी चुनावी बुख़ार पूरी तरह उतरा भी न था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने बेतुके बयान से भाषाई राजनीति को गर्मा दिया है। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर दक्षिण भारत में हिन्दी भाषा को थोपने का आरोप लगाते हुए कहा है कि तमिलनाडु एक और भाषा युद्ध के लिये तैयार है। दक्षिण भारत में और ख़ास तौर पर तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध जग जाहिर है। स्वातंत्र्योत्तर काल से ही द्रविड़ संस्कृति और भाषाई प्रतिबद्धता के नाम पर विभिन्न राजनैतिक दल चुनावी रोटियाँ सेकते रहे हैं। हालाँकि कालांतर में सामाजिक स्तर पर इस भाषाई जड़ता का ख़ामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ा है।

ताज़ा भाषाई विवाद पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के साहित्यिक सांस्कृतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया उभरकर सामने आई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉ. देवेन्द्र दीपक ने स्टालिन के इस आरोप को नितांत भ्रामक बताया है कि हिन्दी और संस्कृत के कारण उत्तर भारत की 25 भाषाएँ नष्ट हो गयी हैं। वे जिन्हें भाषा कह रहे हैं, वह हिन्दी की बोलियाँ हैं और अपने-अपने क्षेत्र में आसीन हैं। दरअसल, स्टालिन के संस्कृत और हिन्दी के विरोध के पीछे उनका सनातन द्वेष है।

स्टालिन का यह कहना भी एक सफेद झूठ है कि हिन्दी उन पर थोपी जा रही है। नयी शिक्षा नीति, जिसमें पढ़ाई के लिये त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया है, के सूत्रधार स्वयं तमिलभाषी है। नई शिक्षा नीति में भाषा का पक्ष लोकतांत्रिक है। त्रिभाषा सिद्धांत में हिन्दी कहीं भी अनिवार्य नहीं है। तमिलनाडु के स्कूलों में बच्चे जो चाहे वह भाषा पढ़ें। अब इसमें हिन्दी को थोपने की बात कहाँ से आ गई?

'शिक्षा की नव क्रांति का शंखनाद' पुस्तक के लेखक और पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने स्टालिन के बयान को भारत विरोधी बताते हुए कहा है कि तमिलनाडु ने तो बहुत पहले से अपने यहाँ द्विभाषा फार्मूला लागू कर तमिल और अंग्रेजी को स्वीकारते हुए हिन्दी को सिरे से नकार दिया था। भाषाई द्वेष के चलते आप लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट भले ही कबाड़ सकते हो, लेकिन घृणा की राजनीति की भी आखिर कोई सीमा तो होनी चाहिये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तमिल संगमम् आयोजित कर वहाँ तमिल विद्वानों को आमंत्रित कर उनका मान-सम्मान किया था।

इस मामले में मप्र साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे की राय प्रामाणिकता और तथ्यों पर आधारित है। वे कहते हैं- 'हिन्दी, तमिल और संस्कृत सभी हमारी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं। संस्कृत ने सदैव दक्षिण की भाषाओं को माँ की तरह पोषण दिया है। दक्षिण की भाषाओं में 'नाभि नाळ सम्बन्धम' जैसे शब्दयुग्म सहज लोक प्रचलित हैं। स्टालिन के आराध्य के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व से यह नाभि नाळ संबंध बना हुआ है। 'वाल्मिकी रामायण' प्रथम राम कथा है। संस्कृत के बाद उसका प्रथम अनुवाद 'कम्ब रामायण' है, जो दक्षिण के संस्कृत से जुड़ाव का प्रतीक है। तमिलनाडु में रामायण के प्राचीनतम संदर्भ हमें संगम कालीन साहित्य में मिलते हैं।'

सप्रे संग्रहालय के निदेशक और दादा माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका 'कर्मवीर' के डिजिटल संस्करण के संपादक अरविंद श्रीधर मानते हैं कि तमिलनाडु अथवा किसी भी दक्षिणी राज्य में हिन्दी का विरोध केवल सियासत के लिए किया जाता रहा है। यह आज से नहीं सालों से हो रहा है। आम धारणा के अनुसार दक्षिण भारतीय भाषाएँ संस्कृत के ज्यादा निकट हैं। भाषाई सौहार्द ही हिन्दी की स्वीकार्यता का विस्तार कर सकता है।

भाषा युद्ध की चेतावनी को लेकर अपने सामयिक आलेख में सुधि पत्रकार और राजनीतिक मामलों के टिप्पणीकार अजय बोकिल ने दो टूक लिखा है-'हिन्दी को लेकर तमिलनाडु का विरोध 1937 से है। वह देश में अकेला ऐसा राज्य है, जहाँ स्कूलों में राजभाषा और अघोषित रूप से राष्ट्रभाषा का स्वरूप ले रही हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती। इससे नुकसान उन बच्चों का होता है, जो तमिलनाडु के बाहर अन्य राज्यों में नौकरी-धंधा करना चाहते हैं। नतीजा यह है कि विद्यार्थी निजी स्तर पर हिन्दी सीख रहे हैं। दक्षिण भारत? हिन्दी प्रचार समिति द्वारा आयोजित हिन्दी परीक्षा में तमिल विद्यार्थियो की बढ़ती संख्या इसका प्रमाण है। निहितार्थ यही कि तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध मुख्यतः राजनीतिक है और द्रविड़ राजनीति की प्रासंगिकता को बनाये रखने की चेष्टा भर है।'

प्रकारांतर से यही बात मध्य प्रदेश लेखक संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र गट्टानी की फौरी प्रतिक्रिया में भी झलकती है- 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को पता होना चाहिये कि जब दक्षिण की भाषाएँ संस्कृत से नष्ट नहीं हुईं तो उत्तर भारत की भाषाएँ कैसे नष्ट हो गईं? स्टालिन के ऐसे बेतुके और राजनीति से प्रेरित वक्तव्य को भीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है।'

हिन्दी सेवियों की स्वैच्छिक संस्था 'हिन्दी परिवार' के संस्थापक अध्यक्ष हरेराम वाजपेयी के तेवर तो और भी गरम हैं- 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भाषा और संस्कृति का इतिहास मालूम नहीं है। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है। लेकिन जो अपनी माँ को माँ नहीं कह सकता वह दूसरे की माँ को क्या सम्मान देगा? 'हिन्दी परिवार' इन्दौर के महासचिव संतोष मोहंती भी कहते हैं कि वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए ही यह भाषाई मुद्दा उठाया गया है।'

आकाशवाणी के पूर्व समाचार वाचक, कवि, लेखक एवं स्तंभकार संदीप श्रोत्रिय भाषा की गरिमा को रेखांकित करते हुए कहते हैं- 'कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा को नष्ट नहीं करती, बल्कि वे साथ-साथ चलते हुए एक दूसरे को समृद्ध ही करती हैं। लेकिन जब राजनीति सतह पर आती है तो राजनेता एक दूसरे को शत्रु की तरह दिखाने और भाषा का इस्तेमाल हथियार की तरह करने से भी नहीं चूकते। मैंने नई दिल्ली के भारतीय जन संचार संस्थान में संस्कृत के समाचार वाचक बलदेव आनंद सागर से तमिलनाडु में त्रिची से आये संवाददाता को इस मुद्दे पर कई दिनों तक लड़ने की हद तक बहस करते देखा है कि द्रविड़ संस्कृत से ज़्यादा पुरानी भाषा है।'

वरिष्ठ साहित्यकार और गीतकार डॉ. रामवल्लभ आचार्य हिन्दी भाषा के महात्म्य को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं। उनका कहना है- 'क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व क्षेत्रवाद की राजनीति पर ही टिका है। यदि दक्षिण भारत के लोग आज के आधुनिक युग में हिन्दी का विरोध करने के बजाय उसे संपर्क भाषा के रूप में अपनाते हैं तो इससे उनका ही भला होगा। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से उनकी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ होगी।'

लघु कथा शोध केंद्र के सचिव घनश्याम मैथिल 'अमृत' के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बयान पूर्णतः राजनीति से प्रेरित और दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्कृत तो भारत वर्ष की भाषा ही नहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत और सभी प्रांतीय भाषाओं की जननी है। हमारी भाषाओं और बोलियों का असल नुकसान तो अंग्रेजी ने किया है, जो हिन्दी की जगह देश की सम्पर्क भाषा बन बैठी है।

वरिष्ठ साहित्यकार प्रभु दयाल मिश्र भी ताजा भाषाई विवाद से व्यथित हैं- 'स्टालिन की उत्तर भारतीयों में फूट डालने की कुटिल चाल सभी भारतीय अच्छी तरह से समझते हैं। तमिल भाषा और संस्कृति का कोई विरोध उत्तर भारत में नहीं है। यह भेद बुद्धि हेय और अपराध भाव जनित ही है जिसे समस्त सच्चे भारतीय बखूबी समझते हैं।'

आकाशवाणी के समाचार संपादक संजीव शर्मा भाषा को कल-कल बहती नदी की तरह मानते हैं। कुछ यही हाल आंचलिक भाषाओं का है। वे अपने क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित हैं और विकास एवं विस्तार के क्रम में हिन्दी में व्यापक रूप से घुल मिल गई हैं। भाषा कोई जमींदार या क्रूर शासक नहीं है जो कमजोर को दबाने का प्रयास करे। बल्कि हिन्दी तो माँ के आंचल सी है। यदि कोई क्षेत्रीय भाषा विकास की इस दौड़ में पीछे रह गई है तो उसका ठीकरा हिन्दी पर नहीं फोड़ा जा सकता।

कवि, कथाकार, व्यंग्यकार गोकुल सोनी बताते हैं कि तमिलनाडु में हिन्दी भाषियों के प्रति जितना द्वेष का भाव अशिक्षित और कम पढ़े लिखे लोगों में है, उतना वहाँ के शिक्षित लोगों में नहीं है। वे टूटी फूटी अंग्रेजी गर्व से बोल सकते हैं पर हिन्दी से उनको बैर है। 1999 में मैं सर्वभाषा सम्मेलन में भाग लेने बैंगलोर गया था। वहाँ देश के हर राज्य से 15-20 साहित्यकार आये थे। मध्यप्रदेश से भी हम एक दर्जन साहित्यकार थे। आयोजन स्थल पर हमें यह देखकर घोर निराशा हुई कि लंबे चौड़े बैनर पर करीब 15 भाषाओं में 'सर्व भाषा सम्मेलन' लिखा था, पर उसमें हिन्दी गायब थी।

हिन्दी की उपेक्षा से हमें इतनी पीड़ा हुई कि हमने एक साथ खड़े होकर विरोध करने तथा सम्मेलन का बायकाट करने का निर्णय किया। तब वहाँ मौजूद मुख्यमंत्री को स्वयं माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने वायदा किया कि मध्यांतर के बाद आपको बैनर पर हिन्दी में नाम लिखा मिलेगा। मध्यांतर के बाद हमें हिन्दी में नाम लिखा हुआ तो मिला परंतु सबसे नीचे और छोटे अक्षरों में। व्यंग्यकार डॉ. हरीशकुमार सिंह का मानना है कि स्टालिन ने हिन्दी द्वारा संस्कृत सहित 25 भारतीय भाषाओँ को निगलने की बात राजनीतिक पैंतरे के रूप में कही है। एक अन्य व्यंग्यकार प्रेमचंद द्वितीय के अनुसार तमिलनाडु के सीएम का बड़बोला बयान दशकों से हाशिये पर पड़े भाषाई विवाद को हवा देने वाला है। देश के 53 करोड़ से अधिक लोगों की मातृभाषा हिन्दी है, वहीं विश्व में 64 करोड़ से अधिक लोग हिन्दी बोलते हैं। अब तो वक्त हिन्दी के विरोध का नहीं, वरन आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने का है।

शाश्वत सृजन के संपादक और साहित्यकार संदीप सृजन कहते हैं कि दक्षिण भारत में हिन्दी विरोधी आंदोलन केवल राजनीति तुष्टिकरण का खेल है। हिन्दी की मंशा कभी अन्य भाषाओं को खत्म करने की नहीं रही है। उज्जैन के लेखक एवं स्तंभकार सुभाष चंद्र जोशी भी इस बात से सहमत हैं कि तमिलनाडु में भाजपा के बढ़ते प्रभाव से भयभीत स्टालिन का वक्तव्य अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का प्रयास मात्र है।

दुष्यंत स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के संयुक्त सचिव और अध्येता सुरेश पटवा को लगता है कि यह शुद्ध राजनीति है। पचास से अधिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कर चुके दिनेश मालवीय 'अश्क' इसे केवल एक तुच्छ राजनीतिक चाल मानते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार एवं दोहाकार प्रभु त्रिवेदी का अभिमत है कि हिन्दी के प्रति राष्ट्रीय अनुराग और उसके बढ़ते हुए वैश्विक प्रभुत्व को देखकर स्टालिन जैसे क्षेत्रीय राजनेता को क्षुद्र राजनैतिक बयानों से परहेज़ करना चाहिए। अन्यथा वह समय दूर नहीं, जब सनातन के साथ संस्कृत और हिन्दी दोनों का अधिकार क्षेत्र बढ़ जाएगा।

इसके विपरीत अखिल हिन्दी साहित्य सभा, अमरावती की संस्थापक अध्यक्ष शीला डोंगरे तमिलनाडु के हिन्दी विरोध को जायज ठहराती हैं, क्योंकि यह राज्य की भाषाई पहचान, सांस्कृतिक अधिकारों और संविधान द्वारा प्रदान किए गए संघीय ढांचे से जुड़ा मसला है। उनके लिए यह विरोध अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने की कोशिश है। हालाँकि वे यह भी कहती हैं कि राष्ट्रीय एकता और संवाद के दृष्टिकोण से हिन्दी को एक साझा भाषा के रूप में बढ़ावा देना समझदारी हो सकती है। इसलिए, इस विरोध को जायज या नाजायज कहने से पहले, यह महत्वपूर्ण है कि हम राज्य की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, और संवाद के माध्यमों के बीच संतुलन बनाए रखें।

विडम्बना यही कि आज़ादी के 78 साल बाद भी हिन्दी को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाना तो दूर; भारत में ही जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ लोग उस पर अन्य भाषाओँ को नष्ट करने के बरगलाने वाले आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे..! यह कड़वा यथार्थ आँखें खोलने वाला भी है और आक्रोशित करने वाला भी..!!

दूषित पानी की समस्या को लेकर मुलताई के तिलक और शास्त्री वार्ड में पहुंचे कलेक्टर

कलेक्टर ने घर-घर जाकर प्रभावितों से की मुलाकात, आरआई को तत्काल किया निलंबित

बैतूल। मुलताई के तिलक और शास्त्री वार्ड में दूषित पानी से लोगों को उल्टी दस्त होने की घटना सामने आने पर कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रविवार को मुलताई पहुंचकर प्रभावित वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने घर.घर जाकर प्रभावित रहवासियों से चर्चा की और उनका हालचाल जाना। साथ ही गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराए जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अमले को दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड में स्थित नालियों और वॉल चैंबरों पानी की टंकी को भी देखा। वॉल चैम्बरों के आस.पास गंदा पानी डालने वालों के विरुद्ध

कार्रवाई किए जाने के निर्देश नगर पालिका के अधिकारियों को दिये। इसके अलावा पानी की टंकी की सफाई करने प्रभावित वार्डों की पुरानी पाइप लाइन बदलने के भी निर्देश नगर पालिका को दिए गए। इस दौरान लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर ने नगरपालिका के आरआई को तत्काल निलंबित किए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अनीता पटेल पीएचईए जल संसाधन विभाग नगर पालिका सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

वार्ड में 24 घंटे मौजूद रहे पैरामेडिकल स्टाफ

शास्त्री और तिलक वार्ड में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सीएमएचओ डॉ. रविकांत उईके को प्रभावित वार्डों में 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहने इन वार्डों का सतत मॉनिटरिंग करने और मरीज को दवाई उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा पीएचई विभाग के अधिकारियों को वार्ड में अलग.अलग जगह से पानी के सैंपल लेने तथा वार्ड में दवाई वितरित करने के निर्देश दिए।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों से की चर्चा

निरीक्षण के पूर्व कलेक्टर श्री सूर्यवंशी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जहां उन्होंने सामान्य वार्ड और आईसीयू ग्रह चिकित्सा इकाई में भर्ती उल्टी.दस्त के पीड़ित मरीजों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को उपचार में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जाए इसके लिए पर्याप्त मात्रा में एंबुलेंस की व्यवस्था रखने के निर्देश सीएमएचओ को दिए गए।

खरसाली के फिल्टर प्लांट एवं हरदौली डैम का किया निरीक्षण

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने मासोद नाका स्थित पानी की टंकी ग्राम खरसाली में स्थित वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सूर्यवंशी ने केमिकल हाउस पानी स्टोर मेन कंट्रोल पैनल में पहुंचकर जानकारी ली। इस दौरान नगर पालिका के अधिकारियों को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने हरदौली डैम पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका पीएचई मत्स्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

मान्यता नवीनीकरण नहीं कराने वाले स्कूलों की 31 मार्च को खत्म हो जायेगी मान्यता

जिले के 24 स्कूल होगे बंद, अंधकार में सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य

बैतूल। निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों का भविष्य अधर में जा पहुंच गया है। जिन स्कूलों में यह बच्चें अब तक पढ़ाई कर रहे थे, उन स्कूल संचालकों द्वारा इस साल नई मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है, जिससे जिले के करीब 24 निजी स्कूलों में ताला लग जायेगा। जिला शिक्षा केंद्र बैतूल के डीपीसी जितेन्द्र भनारिया ने बताया कि बैतूल जिले में कुल 342 निजी स्कूल संचालित थे, जिसमें से 318 स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किये है, वहीं 24 स्कूलों ने समय-सीमा तक आवेदन नहीं किये थे, जिससे 31 मार्च 2025 को इन स्कूलों की मान्यता स्वत- ही समाप्त हो जायेगी। ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने वाले सैकड़ों गरीब बच्चों (आरटीई वाले बच्चों) को अब दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इधर आवेदन न करने वाले स्कूल संचालकों का कहना है कि मान्यता नवीनीकरण को लेकर बदले गए नियमों के चलते परेशानी खड़ी हुई है। इसमें रजिस्टर्ड किरायानामा, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनिवार्यता सहित अन्य और कारण भी शामिल हैं। मान्यता नवीनीकरण न करवाने से बच्चों के साथ-साथ इन स्कूलों में काम करने वाले सैकड़ों युवाओं के बेरोजगार हो जाने की बात भी उनके द्वारा कही गई है।

जटिल नियमों के चलते नहीं किया मान्यता के लिए आवेदन- शासन द्वारा इस वर्ष स्कूल की मान्यता के लिए बनाए गए नियमो में स्कूल भवन मानक अनुसार सुरक्षित होना, कार्यालय कक्ष व प्रधानाध्यापक कक्ष होना जरूरी है। इसके अलावा स्वच्छ भोजन कक्ष व स्टोर रूम अनिवार्य किया गया था। स्कूल का स्वयं का भवन है, तो भवन व भूमि के समस्त दस्तावेज, किराए का स्कूल भवन होने की स्थिति में तीन साल के लिए किराएदारी का रजिस्टर्ड अभिलेख और खेल मैदान का होना अनिवार्य है। साथ ही स्कूल में पर्याप्त पठन-पाठन सामग्री, खेलकूद सामग्री, पुस्तकालय, समाचार पत्र, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, प्रति 50 विद्यार्थी पर एक प्रसाधन की व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा उपकरण व पर्याप्त फर्नीचर अनिवार्य है। इसके अलावा छात्र संख्या के हिसाब से कक्षावार एवं विषयवार प्रशिक्षित शिक्षक व पूर्णकालिक प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक, शिक्षकों का जीओ टेगिंग व ई-केवायसी आदि अनिवार्य किए गए थे।

31 मार्च 2025 को स्वत- ही समाप्त हो जाएगी मान्यता- निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए लेट फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि निकल चुकी है। नए नियमों के साथ जिले के 318 स्कूलों ने मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। 24 स्कूलों ने मान्यता के जटिल नियम होने से स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। अब इन स्कूलों की मान्यता 31 मार्च 2025 को स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद यह नए शिक्षा सत्र से स्कूल संचालित नहीं कर सकेंगे। डीपीसी जितेन्द्र भनारिया ने बताया कि 296 स्कूलों ने आवेदन लॉक किया है। जिन स्कूल संचालकों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किये है, इसके लिए स्कूल संचालक स्वयं ही जिम्मेदार है।

इनका कहना -

जिले के 24 स्कूल संचालकों ने आवेदन नहीं किये है। शासन ने आवेदन के लिए तिथि भी बढ़ाई थी। 25 फरवरी 2025 को लेट फीस के साथ अंतिम तिथि थी। लेकिन स्कूल संचालकों ने आवेदन नहीं किये है। ऐसे में इन स्कूलों की 31 मार्च को स्वत- ही मान्यता रद्द हो जायेगी। हमारे पास अभी तक जितने भी आवेदन आये थे, उसमें से लगभग 50 फीसदी आवेदन का वेरिफिकेशन किया जा चुका है।

- **जितेन्द्र भनारिया,** डीपीसी, जिला शिक्षा केंद्र बैतूल

अश्लील वीडियो भेजकर साइबर ठगी

युवक ने सदमे में किया आत्महत्या का प्रयास, काटा गला, हालत गंभीर

बैतूल- सारणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 के निवासी युवक राजा सूरे ने साइबर अपराध में फंसकर अपना गला ही काट लिया। शनिवार को एमपीइबी हॉस्पिटल, सारणी से प्राप्त एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार, राजा पिता दीपक सूरे उम्र 22 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 5, सारणी ने आत्महत्या का प्रयास किया। उसने अपने हाथ और गले पर स्वयं ब्लेड से वार किए। परिजनों द्वारा उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बैतूल और फिर भोपाल रेफर कर दिया गया। वर्तमान में पीड़ित की स्थिति नाजुक है। थाना प्रभारी जयपाल इनवाती ने बताया कि पीड़ित को वीडियो कॉल और वॉयस कॉल के माध्यम से डीएसपी बनकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। आरोपियों ने डीएसपी बनकर 20 हजार रुपए की मांग की जा रही थी और भुगतान न करने पर पीड़ित का आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। ब्लैकमेल और मानसिक दबाव के कारण पीड़ित ने यह आत्मघाती कदम उठाया। पीड़ित के मोबाइल की जांच में आरोपियों द्वारा वीडियो कॉल, चैट और धमकी भरे संदेश भेजने के प्रमाण मिले हैं। व्हाट्सएप चैट से पता चला कि ब्लैकमेलर बार-बार संपर्क कर रहे थे। संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी ट्रैकिंग की जा रही है। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों पर बीएनएस से संबंधित धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। उपनिरीक्षक सुनील गौर के नेतृत्व में एक टीम राजस्थान रवाना की गई है, राजस्थान पुलिस से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साइबर सेल को डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने और आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच के निर्देश दिए गए हैं।

साइबर अपराध से बचाव के लिए पुलिस की अपील

सारनी थाना प्रभारी जयपाल इनवाती ने लोगों से साइबर अपराध से बचाव के लिए अपील करते कहा है कि ऑनलाइन फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग से सतर्क रहें। अजनबियों से वीडियो कॉल पर बात करने और निजी जानकारी साझा करने से बचें। यदि कोई व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है या साइबर फ्रॉड में फंसा रहा है, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

सीजीएसटी प्रिंसिपल कमिश्नर की मनमानी

असम्मान पूर्ण व्यवहार को लेकर व्यापारिक संगठनों व टैक्स बार एसोसिएशन में गहरा आक्रोश

बैतूल। बैतूल जिले के प्रमुख व्यापारिक संगठनों और टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों ने सीजीएसटी प्रिंसिपल कमिश्नर द्वारा की गई अभद्रता, भ्रष्टाचार व संरक्षण को बढ़ावा देने और कर पेशेवरों पर दबाव बनाने के गंभीर मुद्दे को लेकर जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से आज मुलाकात की।

इस दौरान बैतूल सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री श्री डीडी उइके सहित जिले के सभी विधायकों ने इस गंभीर मामले को उच्च स्तर तक ले जाने का आश्वासन दिया। सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वे इस मामले को वित्त मंत्रालय और संबंधित उच्चाधिकारियों तक पहुँचाकर तत्काल कार्रवाई की मांग करेंगे।

मुद्दे की पृष्ठभूमि:- सीजीएसटी प्रिंसिपल कमिश्नर श्री राकेश गोयल हाल ही में बैतूल आए थे। उनका दौरा सीजीएसटी इटारसी में पदस्थ अधीक्षक श्री नितिन श्रीवास्तव के विरुद्ध व्यापारियों द्वारा की गई अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के संदर्भ में था।

हालांकि, इस बैठक के दौरान टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों को टालने का प्रयास किया गया और कई व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की गईं।

व्यापारियों द्वारा जीएसटी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए जाने पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

रिश्वतखोरी से संबंधित मामलों को लेकर चर्चा में टालमटोल की गई।

राज्य सरकार की नई निवेश नीति के तहत व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी कटाक्ष किए गए।

व्यापारिक संगठनों ने जताया कड़ा विरोध - मामले को लेकर बैतूल जिले के प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने अभूतपूर्व समर्थन जताया और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो एक दिन के संपूर्ण जिला बंद का आह्वान किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों ने दिया आश्वासन- सभी जनप्रतिनिधियों ने व्यापारियों और कर विशेषज्ञों के सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। साथ ही भ्रष्ट अधिकाररियों के असहयोग के कारण जिले के कर राजस्व में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की बात कही। अब यह मामला वित्त मंत्रालय, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्र सरकार के उच्चाधिकारियों तक ले जाया जाएगा।

टैक्स बार एसोसिएशन व व्यापारिक संगठनों ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार के खिलाफ यह संघर्ष जारी रहेगा, जब तक कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती।

(व्यापारिक संगठन एवं टैक्स बार एसोसिएशन)

बैठक में शामिल प्रमुख पदाधिकारी

श्री राजीव खंडेलवाल, अध्यक्ष, टैक्स बार एसोसिएशन, श्री प्रदीप खंडेलवाल, अध्यक्ष, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन श्री अनिल बंगड़, सचिव, टैक्स बार एसोसिएशन, श्री मनोज भार्गव, अध्यक्ष, कैट, श्री बंटी मोटवानी, अध्यक्ष, जनरल एवं किराना व्यापारी संघ, श्री प्रवीण गुगनानी, सचिव, जनरल एवं किराना संघ, श्री अरुण गोठी, अध्यक्ष, सोना यापारी संघ, श्री राजकुमार अग्रवाल, संरक्षक, पेट्रोल पंप व्यवसायी संघ, श्री राजेश आहूजा, अध्यक्ष, ऑटोमोबाइल संघ, श्री मनजीत सिंह साहनी, अध्यक्ष, दवाई विक्रेता संघ, श्री ब्रज आशिष पांडे, अध्यक्ष, जिला उद्योग संघ, श्री अतीत अग्रवाल, अध्यक्ष, सीमेंट एवं लोहा विक्रेता संघ, श्री संजय पगारिया, अध्यक्ष, कपड़ा व्यापारी संघ, श्री राजा साहू, अध्यक्ष, फर्नीचर संघ श्री राजेश मस्की श्री सचिन मालवीय, श्री नवीन तातेड़, गम्फू पाठा, श्री दीपक खुराना, श्री विवेक जैन श्री बी एल पंवार, सीए धर्मेंद्र माहेश्वरी, सीए विजय माथनकर, सीए अनुराग पुरोहित, सीए निकुंज खंडेलवाल, सीए शुभम अग्रवाल, सीए दीपक अग्रवाल, श्री दिनेश पंडागरे, सीए करण पांडे, सीए अर्जुन पांडे, सीए शिवम गुप्ता, श्री नेकराम आर्य, श्री मनोज डफरे, श्री पृथ्वी असोले, श्री राजेश देशमुख, श्री भूषण पंडागरे, श्री टिकेंद्र देशमुख, सीए श्रीमति नेहा खासकलम, श्री संजय अग्रवाल, श्री अनीस सिनोटिया, श्री योगी खंडेलवाल व अन्य प्रमुख व्यापारी एवं कर सलाहकार उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

व्हीसी के माध्यम से दिशा-निर्देश

विदिशा (निप्र)। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री विवेक कुमार पोरवाल के द्वारा आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों की राजस्व वसूली की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने राजस्व प्राप्तियां वित्तीय वर्ष 2024-25 राजस्व वसूली के संबंध में जिलों में क्रियान्वित कार्यों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए समयावधि में वसूली के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री और आरओआर लिकिंग के कार्यों के संपादन के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए हैं। उक्त व्हीसी के दौरान विदिशा के एनआईसी व्हीसी कक्ष में कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह सहित संयुक्त कलेक्टर द्वय श्रीमती मोहिनी शर्मा, श्रीमती निकिता तिवारी, डिप्टी कलेक्टर श्री संतोष बिटोलिया एवं एसएलआर श्रीमती कृष्णा रावत मौजूद रहे।

महिलाओं को किया वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक

सीहोर (निप्र)। वित्तीय समावेशन विकास विभाग द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी की थीम पर सीहोर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिलाओं को वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करने के लिए विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान वित्तीय समावेशन एवं विकास विभाग भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल द्वारा महिलाओं को वित्त के बारे में बचत करने एवं ऋण लेने तथा चुकाने के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही महिलाओं को विभिन्न वित्तीय योजनाएं, घर का बजट बनाना, बचत की आदत, डिजिटल साक्षरता, साइबर धोखा-धड़ी, जीवन बीमा, कौशल निर्माण क्रेडिट स्कोर सहित अनेक शासकीय योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान आरबीआई के एजीएम श्री धीरज गुप्ता, रिजर्व बैंक भोपाल से श्रीमती रोशनी हजेला, एलडीएम श्री अरुण कुमार शर्मा, आरटी निदेशक श्री ओमप्रकाश प्रजापति सहित महिलाएं उपस्थित रहीं।

निरोगी काया अभियान 31 मार्च तक 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की नि:शुल्क

सीहोर (निप्र)। निरोगी काया अभियान 20 फरवरी से 31 मार्च तक संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिकों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। अभियान में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गैर-संचारी रोगों की निःशुल्क जाँच की जायेगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गैर-संचारी रोगों की समय पर पहचान और निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करना है। ये बीमारियाँ प्रारंभिक अवस्था में बिना लक्षणों के होती हैं, लेकिन आगे चलकर हृदय रोग, लकवा, किडनी व लीवर की बीमारियों का कारण बन सकती हैं। इस अभियान के तहत व्यापक स्तर पर स्वास्थ्यजांच,रोग की शीघ्र पहचान और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभियान का विशेष लाभ जनजातीय एवं वनवासी समुदायों को मिलेगा। इन्हें रोगों की रोकथाम, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और नशे से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे स्वस्थ जीवनशैली अपना सकें।स्वास्थ्य विभाग अभियान को प्रभावी बनाने आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्हें प्राथमिकता से जांच और इलाज की सुविधा दी जाएगी।

खेतों में नरवाई जलाने पर होगी कार्रवाई सैटेलाईट से की जा रही है नरवाई जलाने की मॉनिटरिंग

सीहोर (निप्र)। पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के निर्देशों के अंतर्गत प्रदेश में फसलों विशेषतः धान एवं गेंहूँ की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में जारी निर्देशों के उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान निर्धारित किया गया है। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक व्यवस्था बनाकर बेहतर पर्यावरण जन स्वास्थ्य एवं जीव-जन्तुओं की जीवन सुरक्षा प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/ कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो 5 हजार रुपये और 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उसको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। दण्ड वसूलने के लिये संबंधित व्यक्ति/निकाय/कृषक जिनके द्वारा नरवाई जलाकर पर्यावरण को क्षति पहुँचाई गई है।

संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे एवं तामिल किए गए सूचना पत्रों की सूची अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संचालक कृषि को प्रस्तुत करेंगे।कृषि विस्तार अधिकारी, संबंधित ग्राम के हल्का पटवारी एवं पंचायत सचिव के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित थाने से पुलिस बल भी साथ में लिया जा सकता है।आदेश में कहा गया है कि नरवाई जलाने से किसानों को रोकने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। भारत सरकार की संस्था आईसीएआर-क्रीम्स द्वारा देश में नरवाई में आग लगाने की मॉनिटरिंग सैटेलाईट के माध्यम से की जा रही है।

20 प्रतिशत बढ़ाकर किया गया जिले के 19 समूहों की शराब दुकानों का ठेका

सीहोर (निप्र)। नवीन आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के अनुसार जिले के 22 कम्पोजिट मदिरा दुकानों के समूहों के वर्ष 2024-25 की लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्तमान लाइसेंसियों से नवीनीकरण आवेदन प्राप्त किए गए थे। जिसमें कुल 22 समूहों जिनका आरक्षित मूल्य 2,91,70,07,056 रूपये था जिसके विरूद्ध 19 समूहों जिनका आरक्षित मूल्य 2,33,55,63,367 रूपये है। इसके लाइसेंसियों द्वारा नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत किए गये थें। जिला आबकारी अधिकारी दीप सिंह राठौर ने बताया कि नवीनीकरण आवेदन रहित कुल 03 समूहों जिनका आरक्षित मूल्य 58,14,43,689 रूपये था, पर अन्य इच्छुक आवेदकों से लॉटरी ऑनलाइन, ऑफलाइन मंगाए गये थे किन्तु निर्धारित समय तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। कलेक्टर श्री बालागुरू के की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा आरक्षित मूल्य के 80 प्रतिशत से अधिक होने पर 19 समूहों की मदिरा दुकानों का निष्पादन किया गया। शेष रहे 03 कम्पोजिट मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य 58,14,43,689 रूपये है। निष्पादन आगामी दिनाकों में ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन के माध्यम से किया जायेगा।

कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया

विदिशा (निप्र)। राजमाता विजय राजे सिंधिया शासकीय कन्या अग्रणी स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 (दूसरे दिवस)भी उत्साह पूर्वक मनाया गया।

यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जन भागीदारी के सक्रिय सदस्य अशोक गोयल जी एवं प्राचार्य डॉक्टर एन पी अरोरा द्वारा सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। विज्ञान दिवस पर अतिथियों द्वारा सेल्फी पॉइंट का अनावरण कर सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञान का प्रचार प्रसार करने की बात कही गई।

विज्ञान संकाय प्रभारी प्रोफेसर नीता दीक्षित द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए छात्रों को शुभकामनाएं प्रेषित की। विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रोफेसर राम आशीष यादव सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र ने सर सीवी रमन जी के बारे में एवं उनकी खोज रमन प्रभाव, उसके उपयोग साथी छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में करियर की विस्तृत जानकारी दी ।

छात्राओं द्वारा विज्ञान दिवस पर आकर्षक वाल पेंटिंग एवं पोस्टर बनाए गए इस अवसर पर छात्राओं में विज्ञान में रुचि पैदा करने हेतु प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।छात्राओं ने सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान आने वाली छात्राओं को ट्रॉफी सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन डॉक्टर विनीता प्रजापति द्वारा किया गया। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर विनीता प्रजापति द्वारा सभी अतिथियों का आभार मानते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक प्राध्यापक एवं सभी अतिथि विद्वान, महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।

एनएचएआई की 1033 हेल्पलाइन सेवा का लाभ लें

विदिशा (निप्र)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 1033 हेल्पलाइन राष्ट्रीय राजमार्गों से यात्रा करने वाले सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए 24 घंटे सातों दिवस सहायता सेवा प्रदान कर रही है। यह हेल्पलाइन दुर्घटनाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1033 हेल्पलाइन को टोल प्लाजा, एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन, क्रेन जैसी अन्य राजमार्ग संचालन सुविधाओं के साथ एकीकृत किया गया है। जिससे जरूरत के अनुसार आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। सड़क उपयोगकर्ताओं की सभी कॉल्स का उत्तर तत्काल दिया जाता है, जिससे उनका सफर अधिक सुरक्षित और सुगम बनता है। 1033 हेल्पलाइन की सहायता से किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण में करायें समझौता

सीहोर (निप्र)। नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को आपसी समझौतो से निराकृत किया जाएगा। विद्युत अधिनियम 2003 धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए अदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।विद्युत वितरण कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 के अंतर्गत अदालत में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रकरणों में ही छूट दी जाएगी।

प्रि-लिटिगेशन स्तर पर : विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छः माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

लिटिगेशन स्तर पर : विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

लोक अदालत में छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी : आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित कनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी।

ई-उपार्जन पोर्टल पर चना एवं मसूर का पंजीयन 10 मार्च तक

सीहोर (निप्र)। रबी वर्ष 2024-25 में चना एवं मसूर का पंजीयन 20 फरवरी से प्रारंभ हो गया है जो 10 मार्च तक ई-उपार्जन पोर्टल पर किया जा रहा है। जिन किसानों ने चना एवं मसूर की बुवाई की है, वह सभी किसान अपना पंजीयन 10 मार्च से पहले ऑनलाइन करा लें। किसान अपना पंजीयन निर्धारित लिंक कें माध्यम से स्वयं भी कर सकते हैं तथा एमपी ऑनलाइन, सुविधा केन्द्रों, सहकारी एवं विपणन समिति द्वारा सचालित केन्द्रों, कॉमन सर्विस सेन्टर, लोक सेवा केन्द्रों, साइबर कैफे पर आवश्यक दस्तावेज सहित जाकर भी करा सकते हैं। कृषि विभाग के उप संचालक श्री केके पांडे ने जानकारी दी कि किसानों को उपार्जित फसल का भुगतान उनके आधार नम्बर से लिंक बैंक खाते में किया जायेगा, इसलिए सभी किसान अपने आधार नम्बर से बैंक खाता तथा मोबाईल नम्बर लिंक कराकर उसे अपडेट रखे ताकि भविष्य में असुविधा न हो।

दिव्यांगजनों के लिये 7 और 8 मार्च को आयोजित होगी सुगम्य यात्रा

सीहोर (निप्र)। दिव्यांगजनों को सार्वजनिक स्थानों, शासकीय कार्यालयों, मॉल और सिनोमाघरों में उनकी सुविधानुसार किस तरह का सुगम्य वातावरण होना चाहिए। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 7 और 8 मार्च 2025 को कलेक्टर के सहयोग से दिव्यांगजन की ÷सुगम्य यात्रा÷ का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक जिले में चुनिंदा दिव्यांगजन को शासन व्यवस्था के अनुसार वाहन उपलब्ध कराकर सार्वजनिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं आयुक्त निःशक्तजन ने बताया कि सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों को सुगम्य वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में ÷सुगम्य यात्रा÷ निकाली जाएगी। इसमें दिव्यांगजन को सरकारी भवनों, कलेक्ट्रेट, तहसील, नगर पालिका, नगर निगम सहित अन्य शासकीय कार्यालयों, सिनेमा घरों, आम पर्यटन स्थलों, पुस्तकालयों, बाजारों सहित अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगजन उपलब्ध साधन सुविधाओं की जमीन हकीकत को देखेंगे।स्थानों के भ्रमण के बाद दिव्यांगजनों द्वारा दी गई सलाह, सूचनाओं का संकलन किया जायेगा, जिनका उपयोग भारत सरकार द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली शहरी विकास नीतियों, डिजाइनिंग एवं विकासात्मक रणनीतियों में शामिल किया जायेगा, जो भविष्य में इस वर्ग के लिये अनुकूल वातावरण निर्माण में सहायक होगी। यात्रा के फोटो यस टू एक्सेस ऐप पर अपलोड कर सकेंगे। यात्राओं पर होने वाले व्यय सीआरएस फंड या एजीपी सब स्कीम से करने के अधिकार कलेक्टर्स को दिये गये हैं।

श्री महेंद्र वशिष्ठ के पक्के घर का सपना हुआ साकार

सीहोर (निप्र)। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए कल्याण के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी उन्हीं योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर पात्र हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि दी जाती है। अपने सिर पर एक पक्की छत होना हर व्यक्ति का सपना होता है। स्वयं का पक्का मकान, जहां वह अपने परिजनों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए पूरी जिन्दगी भर की पूंजी लगाने पर भी पक्का मकान बनाना संभव नहीं हो पाता। प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे ही लोगों के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। सीहोर के अन्नपूर्णा कॉलोनी निवासी श्री महेंद्र वशिष्ठ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अपना पक्का मकान होगा। श्री महेंद्र वशिष्ठ कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके पक्के घर के सपने को साकार किया है। श्री महेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि कच्चे घर में बारिश के मौसम में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बारिश के दौरान कई रातें हमें जागकर बितानी पड़ती थी, कई बार जहरीले जीवों के घर में आने का डर बना रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने हमें इन सब परेशानियों एवं चिंताओं से मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की स्वीकृति मिली और सरकार से मिली आर्थिक सहायता और अपनी थोड़ी बचत जोड़कर उन्होंने अपने सपनों का घर बनाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद घर बनकर तैयार हो गया। आज उनका परिवार एक सुंदर, पक्के घर में रह रहा है और उनकी पत्नी और बच्चे अब सुरक्षित और आरामदायक माहौल में रह रहे हैं। श्री महेंद्र कहते है कि मुझे पक्के घर का मालिक बनने पर गर्व होता है। श्री महेंद्र वशिष्ठ ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद दिया हैं।

एनएचएम की नवीन संविदा नीति-2025 से चिकित्सा कार्मिकों को मिलेगा बेहतर कार्य वातावरण : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

32 हज़ार से अधिक संविदा कर्मचारी होंगे लाभान्वित

सीहोर (निप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवीन संविदा कर्मचारी नीति-2025 का निर्धारण संविदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए किया गया है। नवीन नीति से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्थायित्व आएगा और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। इस नीति का लाभ 32 हज़ार संविदा कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा और उनके परिवारों सहित लगभग 1.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने में सहायक होगा। उन्होंने समस्त संविदा कर्मचारियों से अपील की है कि सभी समर्पित भाव से सेवा करें, जिससे प्रदेश के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें। एनएचएम की नवीन नीति में संविदा कर्मचारियों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। अब कर्मचारियों को हर वर्ष अनुबंध के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध वार्षिक सेवा आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की गई है। कर्मचारियों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए एक अपीलीय अनुक्रम स्थापित किया गया है। संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का अधिकार केवल मिशन संचालक एनएचएम के पास होगा और यह केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा। नवीन नीति में वेतन वृद्धि को भी एक सुव्यवस्थित ढांचे में लाया गया है। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर नियमित वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को नियुक्ति के समय प्रसव के छह सप्ताह बाद (सातवें सप्ताह से) कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वे मातृत्व के शुरुआती दिनों में समुचित देखभाल प्राप्त कर सकेंगी। इसी तरह, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के प्रावधान भी संविदा कर्मचारियों के लिए लागू किए गए हैं।

आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता के लिए अनुकंपा नियुक्ति और एक्स-ग्रेशिया के प्रावधान : प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की सुचारु व्यवस्था के लिए संविदा कर्मचारियों को अंतर-जिला स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है। जिला स्वास्थ्य समिति को जिले में स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक स्पष्ट शिकायत निवारण अनुक्रम निर्धारित किया गया है। आकस्मिक परिस्थितियों में परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति और एक्स-ग्रेशिया सहायता राशि के प्रावधान किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार विशेष अवकाश की सुविधा भी संविदा कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राही सम्मेलन आयोजित

46 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों को आवास निर्माण की दी गई तकनीकी जानकारी

सीहोर (निप्र)। जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन कि निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए क्लस्टर लेवल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास निर्माण के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा सके तथा आवासों का निर्माण समय सीमा में हो सके। सम्मेलन में मकान का नक्शा लेआउट सहित चरण दर चरण निर्माण की पूरी जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आष्टा जनपद के ग्राम खामखेड़ा एवं सिद्धिकगंज में 11 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों, इछावर जनपद के ग्राम रामनगर में 10 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों, भैरूंदा जनपद के ग्राम पिपलानी में 11 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों एवं सीहोर जनपद के ग्राम अहमदपुर में 14 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

हितग्राही सम्मेलन में हितग्राहियों को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीहोर जिले को 24,388 आवासों का नवीन लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य के तहत सीहोर जिले में नवाचार कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए जिले के प्रत्येक कलस्टर में हितग्राही सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। आयोजित हितग्राही सम्मेलन में हितग्राहियों एवं आमजनों को आवास योजना के बारे विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रथम किस्त में प्लिंथ निर्माण के लिए 25,000 रूपये, दूसरी किस्त में दीवार चुनाई के लिए 40,000 रूपये, तीसरी किस्त में छत निर्माण के लिए 40,000 रूपये, चौथी किस्त में मनरेगा एवं मजदूरी भुगतान के लिए 35,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इस अवसर पर ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायक, सचिव, उपयंत्री, मनरेगा अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास प्रभारी, राजमिस्त्री का कार्य करने वाले आजीविका ग्रुप एवं हितग्राही उपस्थित थे।

उपयंत्री ने किया गौशाला का निरीक्षण, वस्तुस्थिती से कराया अवगत

सीहोर (निप्र)। भैरूंदा जनपद के ग्राम पलासीखुर्द स्थित मॉ कृपा देवी गौशाला में गौवंश की भूख प्यास से मृत्यु होने की शिकायत प्राप्त होने पर भैरूंदा जनपद सीईओ श्री प्रबल अजारिया ने उपयंत्री श्री दीपक भाटी को इसकी जांच करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत उपयंत्री श्री भाटी ने इस बारे में वस्तुस्थिती से अवगत कराते हुए कहा कि शिकायत मिलने के पश्चात 27 फरवरी को हल्का पटवारी, सरपंच, ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्रामीणजनों की उपस्थिति में गौशाला का निरीक्षण किया गया है।

॥ मंदिरम् ॥

48

बाबुलनाथ मंदिर, मुंबई

बाबुलनाथ मंदिर एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है और शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो भारत के मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में मुख्य देवता शिव हैं जो बबूल के पेड़ के भगवान के रूप में हैं। यह मालाबार हिल क्षेत्र के पास एक पहाड़ी पर बना है और इसकी एक दिलचस्प कहानी और विस्तृत इतिहास है। मंदिर का निर्माण 200 साल से भी कम समय पहले हुआ था, लेकिन इसकी उत्पत्ति12वीं शताब्दी में हुई थी। बाबुलनाथ मंदिर शिव भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, और महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान खुशी और उत्साह देखने लायक होता है। मंदिर की भव्यता आपको यह भूल जाने पर मजबूर कर देगी किआप कहां हैं, भगवान शिव के शाश्वत निवास, कैलाश पर्वत का भ्रम पैदा करती है।

मित्रता का महत्व प्रतिपादित करते हैं भगवान श्रीकृष्ण : सीएम

डॉ. यादव बोले-प्रकृति से प्रेम और संस्कृति का सम्मान सिखाते हैं नंद के नंदन

- **इस्कॉन मंदिर को कोलार रोड से जोड़ने वाले मार्ग का नाम प्रभुपाद मार्ग होगा**

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने प्रकृति से प्रेम और ग्राम संस्कृति को सम्मान देने की शिक्षा दी है। राज दरबार में सोने-चांदी और मोती माणिक्य के बीच मोर पंख को अपने शीश पर धारण कर सम्मान प्रदान करना प्रकृति से प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्रीकृष्ण का यह भाव बताता है कि मनुष्य मात्र से प्रेम ही प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। भगवान श्रीकृष्ण का सुदामा को सम्मान देना, जीवन में मित्रता के महत्व और मित्र के सम्मान के लिए प्रतिबद्धता को प्रतिपादित करता है। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के प्रसंगों से हमें कई व्यावहारिक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कोलार रोड क्षेत्र में मानसरोवर डेंटल कॉलेज के पास इस्कॉन द्वारा बनाए जा रहे श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के भूमि पूजन के बाद उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे।इस अवसर पर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, इस्कॉन के मध्यप्रदेश प्रमुख गुरु प्रसाद स्वामी महाराज तथा सचिव महामन प्रभु उपस्थित थे। कार्यक्रम में बताया गया कि यह मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्षेत्र में इस्कॉन मंदिर स्थापना की पहल की सराहना करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण, लोगों पर सुख-आनंद, वैभव और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोलार रोड से इस्कॉन मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग का नाम प्रभुपाद मार्ग रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत की सभी दिशाओं में प्रभु श्री राम और भगवान श्रीकृष्ण की उपस्थिति की सहज ही अनुभूति होती है। विश्व में भी वर्षों से भारत, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की धरती के रूप में जाना जाता है, मंदिर निर्माण भगवद्भाव के साकार रूप लेने का माध्यम है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा ऐसी कामना है कि भूमि-पूजन के बाद मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के प्रकटीकरण और मंदिर के लोकार्पण का अवसर शीघ्र ही आएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और सात्विक जीवन प्रणाली के प्रसार में प्रभु पाद के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन विचारों के अनुरूप ही राज्य सरकार, मद्यनिषेध की दिशा में कार्य कर रही है, इसीलिए प्रदेश के 17 स्थानों में शराबबंदी की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ सहयोग से दुग्ध उत्पादन 9 से 20 प्रतिशत तक ले जाने की कार्य योजना का क्रियान्वयन जारी है। यह प्रयास हमारी मूल संस्कृति की ओर लौटने के लिए किया जा रहा है। इससे खेती और पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और दूध की पौष्टिकता से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने में सहयोग मिलेगा।

प्रमुख अभियंता जांचेंगे किसान को डिग्गी में डालने का केस

15 दिन में देना होगा जवाब, कलेक्टर रिपोर्ट में दोषी मिला एसडीओ पहले ही हो चुका निलंबित

भोपाल। सिवनी में किसान को मारकर उसे कार की डिग्गी में ठूंसने वाले जल संसाधन विभाग के एसडीओ को कलेक्टर की जांच में दोषी पाया जाने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया। अब राज्य शासन ने उसके खिलाफ विभागीय जांच करने चार्जशीट जारी कर दी है। प्रमुख अभियंता इस मामले में जांच करेंगे। आरोपी इंजीनियर को 15 दिन के अंदर जबाव देना होगा। समय पर जवाब नहीं मिलने पर प्रमुख अभियंता सीधे कार्रवाई का फैसला कर सकेंगे। दरअसल किसान से अभद्रता करने के घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। सिवनी जिले के केवलारी क्षेत्र में 16 फरवरी,

सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ, जो शनिवार 14 फरवरी का था। वीडियो में तिलवारा दाई तट नहर के एसडीओ श्रीराम बघेल नहर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब स्थानीय किसानों ने उनके सामने सिंचाई की समस्या रखी, तो वे भड़क गए और मारपीट और गाली-गलौज करने लगे। इस दौरान किसान उनके सामने हाथ जोड़ता रहा लेकिन एसडीओ ने उनकी एक नहीं सुनी। इस मामले में उनके विरोध में केवलारी थाने में केस भी दर्ज किया गया और आरोपी को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इसी दिन एक अन्य स्थान पर भी इंजीनियर का किसानों से विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट कलेक्टर सिवनी ने राज्य सरकार को भेजी।

कलेक्टर से मांगी जांच रिपोर्ट में मिला दोषी- इस मामले में सिवनी कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी। आरोपी ने जिस ने किसान को जबरन कार की डिक्की में डाला उसी दिन 11.30 बजे केवलारी डिस्ट्रीब्यूटरी के चैन क्रमांक 255 की जांच करते समय भी एसडीओ बघेल ने किसानों से भी विवाद किया था। इसका भी वीडियो वायरल हुआ। इन दोनों ही मामलों को शासन ने सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल माना, इसलिए इनके विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग विनोद देवड़ा ने जारी आदेश में कहा है कि एसडीओ श्रीराम बघेल 15 दिनों में लिखित जवाब देकर बताएं कि क्या वे इस मामले में मौखिक जांच या व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं।

नई फिल्म पर्यटन नीति से सिनेमा और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री बोले-जीआईएस-भोपाल से फिल्म निर्माण को मिलेगा बूस्ट

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश लंबे समय से फिल्म निर्माताओं के लिए कल्पनालोक बना रहा है। राज्य सरकार की नई फिल्म एवं पर्यटन नीति-2025 ने यहां शूटिंग को व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आकर्षक बना दिया है। उन्होंने कहा कि इस नीति से प्रदेश की छवि बड़े पर्दे पर और भी प्रभावशाली बनकर वैश्विक पटल पर उभरेगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को भी नई ऊंचाइंया मिलेंगीं। मुख्यमंत्री डॉ. ने कहा कि जीआईएस भोपाल से फिल्म निर्माण एवं पर्यटन उद्योग के गोल्डन ग्लोबल गेट की ओपनिंग हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीआईएस-भोपाल का शुभारंभ करते हुए हमें बताया कि भारत के विकास में टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और टूरिज्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्ष 2047 तक भारत की जीडीपी में पर्यटन का योगदान 10 प्रतिशत से अधिक होगा।

जीआईएस-भोपाल में नई नीति बनी करोड़ों के निवेश का आधार- जीआईएस-भोपाल में पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार की नई फिल्म एवं पर्यटन नीति पर प्रेजेंटेशन से फिल्म निर्माता और पर्यटन उद्योग के पुरोधा अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि इससे प्रदेश में और अधिक अनुकूल वातावरण बनेगा, साथ ही इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश होंगे। जीआईएस-भोपाल से पर्यटन, फिल्म-पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 68,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, इससे पर्यटन क्षेत्र में 1.2 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। नई फिल्म-पर्यटन नीति में फिल्मों और वेब-सीरीज के निर्माण के लिए अनुदान राशि बढ़ाई गई है। नई नीति में फीचर फिल्म निर्माण के लिये 5 करोड़ रुपये, वेब सीरीज निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये, टीवी सीरियल निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपये, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के लिए 50 लाख रुपये, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के निर्माण पर, 12 करोड़ रुपये और शॉर्ट फिल्म निर्माण पर 20 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

स्थानीय भाषाओं और विषयों पर फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय भाषाओं-बोलियों में फिल्म बनाने पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने का नई नीति में प्रावधान किया है। इसमें मालवी, बुंदेली, निमाड़ी, बघेली और भीली भाषाओं की फिल्मों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, महिला और बच्चों पर केंद्रित फिल्मों के निर्माण पर भी 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। वर्तमान में मध्यप्रदेश में फिल्म निर्माता आगे आ रहे हैं। मध्यप्रदेश को वर्ष-2022 में 'द मोस्ट फिल्म-फ्रैंडली' राज्य का पुरस्कार मिल चुका है। अब तक 15 हिंदी फिल्मों, 2 तेलुगु फिल्मों और 6 वेब सीरीज को 30 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय अनुदान दिया जा चुका है। प्रमुख फिल्म और वेब सीरीज परियोजनाओं में स्त्री-1 एवं स्त्री-2, भूल-भुलैया-3, सुई-धागा, लापता लेडीज, द रेलवे मैन, पैडमैन, धड़क-2, स्त्री, पंचायत, कोटा फैक्ट्री, गुल्लक और सिटाडेल आदि शामिल हैं।

मध्यप्रदेश में पर्यटन है ग्लोबल-अट्रेक्शन

मध्यप्रदेश में वन्य जीव पर्यटन का अनुभव कराने के साथ साथ यहां पर्यावरण संरक्षण और सह अस्तित्व की अवधारणा पर कार्य किया जाता है। वन्य जीव बिना डर के गांव में विचरण करते हुए नजर आते है। श्योपुर में चीते आस-पास के गांव में तो बाघ भोपाल में शहरी इलाकों में विचरण करते हुए दिखते है। पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन ऐसा सिर्फ मध्यप्रदेश में संभव है। मध्यप्रदेश चीता, बाघ, घड़ियाल, तेंदुआ के साथ वल्चर स्टेट भी है। टाइगर रिजर्व की संख्या में भी वृद्धि हो रही हैं। प्रदेश में डायवर्सिफाइड टूरिज्म रिसोर्सेज के कारण मध्यप्रदेश को देश के साथ ही विश्व की टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन माना जा रहा है। मध्यप्रदेश में खजुराहो, कान्हा, सांची, ओरछा, ग्वालियर, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, अमरकंटक, उज्जैन और ओंकारेश्वर जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं।

पर्यटन में निवेश के मिले आकर्षक प्रस्ताव

राज्य सरकार को पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें अमेज़न प्राइम, जी-5, आईएचएसओएल, ट्रेजर ग्रुप, आईटीसी होटल्स, हिल्टन समूह आदि के 300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। आकर्षक निवेश से निसंदेह मध्यप्रदेश में पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने इंदौर में वॉटर पार्क के लिए 200 क़रोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। नीमराना समूह ने चंदेरी के राजा-रानी महल को विकसित करने के लिए 20 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इवॉल्व बैक रिसॉर्ट्स ने पन्ना टाइगर नेशनल पार्क के पास नए वेलनेस रिसोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

गुना में नेशनल हाईवे से दुल्हन किडनैप, दूल्हे से मारपीट

लड़की कह रही थी-आकाश इसे मत मारो, अशोक नगर से शादी कर राजस्थान जा रहे थे

भोपाल। गुना में रविवार को दिनदहाड़े एक दुल्हन का अपहरण हो गया। इस दौरान दूल्हे से मारपीट भी की। दूल्हा, दुल्हन को लेकर अशोकनगर से राजस्थान के सवाई माधोपुर जा रहा था। इसी दौरान रूठियाई के पास उनकी गाड़ी रुकवाकर कुछ लोगों ने दुल्हन को अगवा कर लिया। मामले में पुलिस ने पांच किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले विक्रम नायक की शादी शनिवार को अशोकनगर के रातीखेड़ा गांव की युवती से हुई थी। शनिवार को राजस्थान से बारात आई थी। शनिवार रात शादी की रस्में हुईं। रविवार सुबह विक्रम अपनी दुल्हन को विदा कराकर अशोकनगर से राजस्थान के लिए कार से निकला था।

अशोकनगर से ही पीछा कर रहे थे किडनैपर्स- जानकारी के मुताबिक कार में ड्राइवर, दूल्हा-दुल्हन, दुल्हन की दादी और मौसी बैठे हुए थे। एक रस्म के चलते दुल्हन के परिवार से इन दोनों को गाड़ी में बैठाया गया था। दूल्हे विक्रम नायक ने बताया कि रविवार सुबह 9:30 बजे वह अशोकनगर से दुल्हन को लेकर निकला था। अपहरणकर्ताओं ने अशोकनगर से ही कार कार पीछा करना शुरू कर दिया था।

स्कॉर्पियो सवारों ने कार रुकवाकर दूल्हे को पीटा- दूल्हे विक्रम ने बताया कि गाड़ी जब गुना के गादेर इलाके में पहुंची, तब भी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। इसके बाद करीब 10:30 बजे नेशनल हाईवे-46 पर गुना जिले के रूठियाई रूठियाई चौकी के आगे अपहरणकर्ताओं ने कार के सामने अपनी कार लगा दी। हमारी कार के पीछे एक बाइक खड़ी कर दी, ताकी हम भाग न पाएं। स्कॉर्पियो से सात-आठ लोग उतरे और उन्होंने चाकू से गाड़ी के विंडो ग्लास तोड़ दिए। उन लोगों ने मुझे कार से उतारा और मेरे साथ मारपीट की। इसके बाद दुल्हन को अपनी कार में बैठाकर भाग निकले। इतना ही नहीं बदमाशों ने हमारी गाड़ी के टायर भी पंक्चर कर दिए।

इस वारदात की सूचना विक्रम ने फौरन पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रूठियाई चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और दूल्हे से पूरी जानकारी ली।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

छत्तीसगढ़ की साय सरकार जनता की सर-आँखों में

राज्य में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा को जिस तरह लोगों ने समर्थन दिया है, उससे साफ़ है कि यहां की करीब 13 महीने पुरानी विष्णुदेव साय सरकार को सर-आँखों पर बैठा लिया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा को करीब 56 फीसदी वोट मिले हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 46 फीसदी वोट मिले थे, हालांकि राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के करीब तीन महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को 52 फीसदी वोट मिले थे। लोकसभा में भाजपा ने राज्य की 11 में से 10 सीटें जीती। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में तो भाजपा की लहर ही चल गई। विष्णुदेव साय सरकार में हर चुनाव में भाजपा का वोट परसेंट बढ़ने का मतलब साफ़ है कि लोग सरकार के कामकाज और नीतियों को पसंद कर रहे हैं। कहते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्लोगन-पार्षद से प्रधानमंत्री और पंचायत से पार्लियामेंट की भी खूब चर्चा रही। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नारे से प्रभावित होकर लोगों ने भाजपा के पक्ष में ईवीएम के बटन दबाए और ठप्पे लगाए। राज्य में भाजपा के वोट परसेंट में जबरदस्त उछाल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। वोट परसेंट बढ़ने को साय सरकार की मजबूती का सूचक भी माना जा रहा है।

भाजपा नेता का कैदी से प्रेम

कहते हैं कि भाजपा के एक नेता का रायपुर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी से प्रेम आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते हैं कि भाजपा नेता जेल में बंद कैदी के सुख-सुविधा के लिए अफसरों को समय -समय पर फोन करते रहते हैं। शुरू में जेल के अफसर दबाव में आकर कुछ मदद कर दी, पर जेल और पुलिस के आला अफसरों को भनक लगने के बाद भाजपा नेता के चहेते कैदी की व्हाट लगा दी। नेताजी के फोन का भी कोई असर नहीं हुआ। नेताजी पार्टी में खासे रसूखदार हैं और नेताजी के आशीर्वाद से जेल जाने से पहले कैदी की दसों अंगुलियां घी में थी।

कलेक्टरी का मोह भारी

कहते हैं धमतरी की कलेक्टर नम्रता गांधी अब शायद ही केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाएं। 2013 बैच की आईएएस नम्रता गांधी को कैबिनेट सेक्रेट्रियेट में उप सचिव बनाए जाने का आदेश 31 जनवरी को हुआ था। आदेश के मुताबिक़ उन्हें तीन हफ्ते के भीतर नई जगह ज्वाइनिंग देनी थी। तीन सप्ताह के समय बीतने के बाद राज्य सरकार ने अब तक उन्हें कार्यमुक्त करने का आदेश जारी नहीं किया है। दुर्ग की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी का भी केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति में जाने के लिए 10 फ़रवरी को आदेश हुआ था। तीन हफ्ते के भीतर इन्हें भी भारत सरकार में ज्वाइनिंग देनी है। ऋचा प्रकाश चौधरी को वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। ऋचा प्रकाश के बारे में भी राज्य सरकार ने अब तक फैसला नहीं किया है। इससे लग रहा है कि दोनों महिला अफसर कलेक्टर बनीं रहेंगी। वैसे भी कलेक्टर के रुतबे के सामने भारत सरकार के उप सचिव के पद को बौना ही माना जा रहा है।

कुंभ स्नान कर चर्चा में कलेक्टर साहब

कहते हैं राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान एक कलेक्टर साहब कुंभ स्नान कर सुर्ख़ियों में आ गए हैं। राज्य के कुछ सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी परिवार सहित कुंभ स्नान को गए, पर वे अकेले गए और आए, त हल्ला नहीं हुआ। बताते हैं कि कलेक्टर साहब एक वीवीआईपी के साथ प्लेन से प्रयागराज गए थे। इस कारण वे सुर्ख़ियों में आ गए। चर्चा है कि कुंभ स्नान के लिए जाने हेतु कलेक्टर साहब ने न तो सरकार से अनुमति ली और ही राज्य निर्वाचन आयोग से। सरकार इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। खबर है कि सरकार के कुछ लोग कलेक्टर साहब के इस काम से खुश नहीं हैं। कलेक्टर साहब उत्तरप्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। ये साहब कांग्रेस राज में तीन जिलों में काफी कम-कम समय के लिए कलेक्टर रहे, फिर उन्हें मंत्रालय में पदस्थ कर दिया गया। इसका फायदा मिला और राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही साहब को एक बड़े जिले की कलेक्टरी मिल गई।

पुलिस मुख्यालय में कमरों की मारामारी

कहते हैं पुलिस मुख्यालय में अफसरों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे कमरों की मारामारी हो गई है। आलम यह है कि डीएसपी स्तर के अफसरों के लिए आरक्षित कमरों में डीआईजी स्तर के अधिकारियों को आबंटित करना पड़ा है। सरकार ने पिछले कुछ महीनों में फील्ड से कई आईपीएस अफसरों को हटाकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ कर दिया। काफी समय तक उन्हें विभाग नहीं मिला था। अब विभाग मिल गया है तो कमरों की समस्या आ गई। बताते हैं कि पुलिस मुख्यालय में इससे पहले एक साथ इतने अधिकारी तैनात नहीं थे। अफसरों की भीड़ के कारण एक छोटे से सेक्शन में एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी को पदस्थ करना पड़ा है। अब प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम क्या करते हैं ,इसका सभी को इंतजार है।

बिना कोषाध्यक्ष के कब तक चलेगी कांग्रेस

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल करीब दो साल से लापता हैं। ईडी उनके पीछे पड़ी है और उनकी तलाश में बताई जाती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने रामगोपाल अग्रवाल की जगह अब तक किसी को प्रदेश कांग्रेस का कोषाध्यक्ष नहीं बनाया है। प्रदेश कांग्रेस बिना कोषाध्यक्ष के ही चल रही है। इस बीच विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव भी निपट गया। अब चर्चा होने लगी है कि बिना कोषाध्यक्ष के प्रदेश कांग्रेस कब तक चलेगी। इस बीच ईडी के अफसर प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय तक जा पहुंचे। सुकमा का राजीव भवन ईडी के निशाने पर है। ईडी के अफसर सुकमा के कांग्रेस भवन के लिए धन की व्यवस्था की तह तक जाना चाहते हैं। अब प्रदेश कांग्रेस में कोषाध्यक्ष नहीं हैं तो ईडी का सामना प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू को करना पड़ा।

आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति कब

कहते हैं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले में कोर्ट ने आठ शराब कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराते हुए पार्टी बना दिया है और उन्हें कोर्ट में आने के लिए समंस जारी करने का आदेश दिया है, पर इस मामले में कुछ जिला आबकारी अधिकारियों और एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी के अपराध में शामिल होने के बाद भी उनके खिलाफ अब तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलना चर्चा का विषय है। कहते हैं अदालत ने भी इस पर टिप्पणी की है और कहा है कि अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में राज्य सरकार को अभियोजन की स्वीकृति देनी है। अब देखते हैं सरकार कब तक अभियोजन की स्वीकृति देती है।

पीए-ओएसडी के फेर में मंत्री जी

कहते हैं कि साय सरकार के कुछ मंत्रियों पर पीए और पीएस भारी पड़ रहे हैं। एक मंत्री को तो पीए के अक्ल से चलने के कारण अपनी किरकिरी करानी पड़ गई। मंत्री जी अपनी ही पार्टी के विधायक के सवालों के फेर में उलझ गए। एक मंत्री जी के ओएसडी साहब ने तो मंत्री जी की जानकारी के बिना बजट प्रपोजल ही बदल दिया। बताते हैं एक मंत्री जी तो बाकायदा अपने एक पीए को खुफ़िया काम में और एक को व्यवस्था में लगा रखा है। एक मंत्री जी बिना आदेश के अपने एक पुराने पीए को अपने साथ अटैच कर रखे हैं। पुराने पीए के कारण मंत्री जी के एक विभाग में विवाद की स्थिति बनी हुई है।